ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ
সাপ্তাহিক
জন জন বিচাৰ

जन जन की बात जन जन तक
साप्ताहिक
जन जन विचार
WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER
Language : Hindi, Assamese & English
WEBSITE : www.janjanvichar.in

VOICE OF ALL, FOR ALL
WEEKLY
JAN JAN VICHAR

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 10 July 2026 :: Year-1 Vol-26 Issue-5 ::शुक्रवार । 10 जुलाई 2026 । शक संवत 1948 । आषाढ़ । कृष्णा । एकादशी । :: पृष्ठ-20 । मूल्य - 15 रुपए

जन चिंतन
धनेश्वर चौधरी

विश्वास की परीक्षा

असम विधानसभा में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने को लेकर शुरू हुआ विमर्श केवल एक प्रशासनिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि राज्य की बहुभाषी पहचान, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे मुद्दों पर जल्दबाजी या राजनीतिक ध्रुवीकरण से अधिक आवश्यकता संवेदनशील संवाद और व्यापक सहमति की है।

असम सदियों से विविध भाषाओं और संस्कृतियों का संगम रहा है। असमिया इस भूमि की आत्मा है। इसके साथ बोडो, बांग्ला, हिंदी, नेपाली तथा अनेक जनजातीय भाषाओं ने राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाया है। इसलिए किसी भी नई भाषा नीति का पहला दायित्व यह होना चाहिए कि स्थानीय भाषाओं की गरिमा और शेष पृष्ठ 2 पर

फिर शुरू हुआ युद्ध

जन जन विचार
...✍ वॉशिंगटन/तेहरान

ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले
होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर तनाव चरम पर
वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर गहराया संकट

पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताजा हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच लागू अंतरिम युद्धविराम प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है।

अमेरिका का दावा है कि ईरान द्वारा तीन व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सैन्य अभियान चलाया गया। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिकी हमलों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है।

दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत समुद्री कच्चे तेल का परिवहन होर्मुज जलडमरूमध्य से होता है। संघर्ष तेज होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार

में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है और वैश्विक व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

कुछ ही समय पहले दोनों देशों के बीच संघर्ष रोकने के लिए अंतरिम समझौता हुआ था, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने उस समझौते को झटका दिया है। यदि हालात जल्द नहीं संभले तो पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा।

चढ़ावा चोरी : आस्था, आरोप और सच की तलाश

जन जन विचार
...✍ अयोध्या/लखनऊ

देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परियोजनाओं में शामिल अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक जांच में कई गंभीर प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी कमियां सामने आई हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप ने पूरे प्रकरण को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति या संस्था की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला ?

मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिदिन बड़ी मात्रा में नकद राशि,

एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट

- चढ़ावे की गणना प्रक्रिया के दौरान कई संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड हुईं।
- सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों द्वारा नकदी छिपाने जैसी गतिविधियों के प्रथमदृष्टया संकेत मिलने की बात कही गई।
- सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं हुआ।
- प्रवेश-निकास जांच, व्यक्तिगत सामान की तलाशी तथा निगरानी व्यवस्था में गंभीर कमियां पाई गईं।
- सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और उसकी नियमित निगरानी में भी लापरवाही के संकेत मिले।
- जांच एजेंसी ने कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की भी आवश्यकता बताई है।

एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है तथा विस्तृत जांच अभी जारी है।

स्वर्ण-रजत आभूषण तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। इनकी गणना और बैंक में जमा करने की निर्धारित प्रक्रिया है।

कुछ सप्ताह पहले चढ़ावे की गणना प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की। प्रारंभिक जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों के बयान तथा बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच की गई।

आठ लोगों पर प्राथमिकी

प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें चढ़ावे की गणना से जुड़े कुछ कर्मचारी और अन्य संबंधित व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस उनके बैंक खातों, लेन-देन तथा अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।

ट्रस्ट की भूमिका पर भी उठे सवाल

जांच रिपोर्ट में केवल कर्मचारियों की भूमिका ही नहीं बल्कि शेष पृष्ठ 7 पर

हिंदी बनी असम विधानसभा की चौथी आधिकारिक भाषा

गुवाहाटी। असम विधानसभा ने अपने कामकाज में हिंदी को चौथी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक में लिया गया।

इस निर्णय के बाद अब विधानसभा की कार्यवाही असमिया, अंग्रेजी, बोडो और हिंदी, इन चार भाषाओं में संचालित की जा सकेगी। विधानसभा अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को अधिक समावेशी बनाना तथा राज्य के विभिन्न भाषाई समुदायों के लिए उसे अधिक सुलभ करना है।

विधानसभा का बजट सत्र 6 जुलाई से 31 जुलाई तक कुल 21 कार्य दिवसों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान 10 शेष पृष्ठ 3 पर

यूसीसी वापस लेने की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के अध्यक्ष एवं बिन्नाकांदी विधायक बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा से उनके कार्यालय में मुलाकात कर विभिन्न जनहित के मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाल ही में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को वापस लेने अथवा उसकी व्यापक समीक्षा कराने की प्रमुख

मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल में दलगांव विधायक मजीबुर रहमान, पूर्व विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम, रफीकुल इस्लाम, अशरफुल हुसैन तथा पार्टी के महासचिव रेजाउल करीम सरकार भी शामिल थे।

यूसीसी पर पुनर्विचार की मांग

एआईयूडीएफ ने अपने ज्ञापन में कहा कि हाल में लागू समान नागरिक संहिता के कुछ प्रावधान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक परंपराओं, व्यक्तिगत कानूनों और सामाजिक रीति-रिवाजों को प्रभावित करते हैं। पार्टी का कहना है कि इस कानून के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि सभी समुदायों की संवैधानिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित हो सके।

संविधान के प्रावधानों का हवाला

ज्ञापन में एआईयूडीएफ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है।

पार्टी ने अनुच्छेद 29 और 30 का भी हवाला देते हुए कहा कि ये प्रावधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। एआईयूडीएफ का मत है कि यूसीसी के कुछ प्रावधान इन संवैधानिक अधिकारों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

सभी पक्षों से संवाद की मांग

एआईयूडीएफ ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि यूसीसी के क्रियान्वयन से प्रभावित होने वाले सभी समुदायों, धार्मिक संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा कर कानून की समीक्षा की जाए।

रोहा में प्रीति पोद्दार ने कराया योगाभ्यास

जन जन विचार
...✍ रोहा

रोहा के महेंद्र हजारिका भवन में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित 100 घंटे (25 दिवसीय) योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के पांचवें दिन तिनसुकिया से आई वरिष्ठ योग प्रशिक्षक प्रीति पोद्दार ने साधक-साधिकाओं को योग एवं प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया।

शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रीति पोद्दार ने लगभग 60 प्रतिभागियों को अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, उज्जायी सहित विभिन्न योग एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया तथा नियमित योग के स्वास्थ्य लाभों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर नौगांव जिला भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के संरक्षक एवं योग प्रशिक्षक ओमप्रकाश जाजोदिया ने भी योग के महत्व पर प्रकाश डाला।

आयोजकों ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अनुभवी योग प्रशिक्षक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, रोहा मारवाड़ी समाज तथा मायुमं (मारवाड़ी युवा मंच) के प्रतिनिधियों ने प्रीति पोद्दार का फूलाम गामोछा, सेलेंग और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में कमल चंद्र शर्मा, सुनील हजारिका, रामनिवास शर्मा, अरूप वैश्य, स्वर्णलता भुइयां, दीपिका हजारिका दास सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, योग शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में साधक-साधिकाएं उपस्थित रहे।

राशिफल

(03-07-2026 से 09-07-2026)

मेष : मानसिक अस्थिरता हो सकती है। आपको अपने काम में अच्छे नतीजे मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता शुभ है।

वृषभ : आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं। नौकरी और व्यापार में प्रगति होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा तथा रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मिथुन : नई योजनाओं पर काम शुरू होगा और करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा तथा परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कर्क : भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। नौकरी और व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी। परिवार में पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह : आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा। व्यापार में लाभ तथा संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

कन्या : काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला : भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग हैं। यात्रा का अवसर मिल सकता है तथा पारिवारिक सुख बना रहेगा।

वृश्चिक : धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक तनाव कम होगा।

धनु : करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है।

मकर : करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक लाभ होगा। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कुंभ : नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मीन : यह सप्ताह मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का रहेगा। करियर और व्यापार में लाभ होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

10 जुलाई (शुक्रवार) : योगिनी एकादशी व्रत
देवराहा बाबा पुण्यतिथि
11 जुलाई (शनिवार) : एकादशी व्रत (वैष्णवों का)
12 जुलाई (रविवार) : प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि व्रत
14 जुलाई (मंगलवार) : भौमवती अमावस्या, गंगा स्नान
15 जुलाई (बुधवार) : गुप्त नवरात्र शुरू, मनोरथ द्वितीया
15 जुलाई (गुरुवार) : रथयात्रा

●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

पृष्ठ 1 का शेषांश...

विश्वास की परीक्षा

अधिकार अक्षुण्ण रहें।

यह भी एक वास्तविकता है कि हिंदी आज देश की प्रमुख संपर्क भाषाओं में से एक है। व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और अंतरराज्यीय संवाद में इसका महत्व लगातार बढ़ा है। असम में भी लाखों लोग हिंदी का उपयोग करते हैं। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर हिंदी के सीमित और व्यावहारिक उपयोग पर चर्चा होना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन यह विमर्श तभी सार्थक होगा, जब इससे किसी समुदाय में अपनी भाषा और पहचान के कमजोर होने का भय उत्पन्न न हो।

भाषा का प्रश्न भावनाओं से जुड़ा होता है। इतिहास गवाह है कि भाषा को लेकर पैदा हुए अविश्वास ने कई राज्यों में लंबे समय तक सामाजिक तनाव पैदा किए हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार हर निर्णय से पहले सभी पक्षों (साहित्यकारों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न भाषाई समुदायों) से व्यापक विचार-विमर्श करे।

राष्ट्रीय एकता का अर्थ भाषाई एकरूपता नहीं, बल्कि विविधता का सम्मान है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अनेक भाषाएं हैं। यदि हिंदी को प्रोत्साहन मिले तो वह अन्य भारतीय भाषाओं के सम्मान के साथ मिले, न कि उनके विकल्प के रूप में। यही भारतीय संविधान की भावना भी है।

असम को आज किसी भाषाई टकराव की नहीं, बल्कि भाषाई समन्वय की आवश्यकता है। निर्णय ऐसा हो जो प्रशासन को सरल बनाए, राष्ट्रीय संवाद को मजबूत करे और साथ ही असमिया सहित सभी स्थानीय भाषाओं की गरिमा और अधिकारों की पूरी रक्षा करे। यही लोकतांत्रिक परिपक्वता होगी और यही असम की बहुरंगी पहचान के अनुरूप भी होगा।

जनमत का सम्मान, भाषाओं का समान सम्मान और संवाद का मार्ग, यही इस बहस का सबसे उचित समाधान है।

'गुंडा टैक्स' से महंगे हो रहे जरूरी सामान : अखिल गोगोई

असम-बंगाल सीमा पर अवैध वसूली का आरोप, मंत्री जयंत मल्ल बरुवा व बीटीसी प्रमुख हाग्रामा मोहिलारी का लिया नाम

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम में अंडों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसागर के विधायक एवं राइजर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुवाहाटी में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दावा किया कि असम-पश्चिम बंगाल सीमा पर कथित 'सिंडिकेट' के माध्यम से की जा रही अवैध वसूली, जिसे उन्होंने 'गुंडा टैक्स' कहा, उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डाल रही है।

गोगोई ने आरोप लगाया कि श्रीरामपुर और बक्सीरहाट प्रवेश द्वारों से असम में आने वाले मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली की जाती है, जिसकी भरपाई अंततः आम उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलकर की जाती है।

अंडे की कीमत को लेकर सवाल

अखिल गोगोई ने दावा किया कि नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के अनुसार एक अंडे की कीमत लगभग रुपए 5.75 होनी चाहिए, जबकि गुवाहाटी में उपभोक्ताओं को रु. 8.50 से रु. 10 प्रति अंडा चुकाना पड़ रहा है।

उनका आरोप है कि सीमा पर प्रति अंडा लगभग रुपए 3 की अवैध वसूली किए जाने के कारण खुदरा बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं।

हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

केवल अंडे ही नहीं, अन्य वस्तुएं भी प्रभावित

गोगोई ने आरोप लगाया कि कथित सिंडिकेट केवल अंडों तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार ब्रॉयलर चिकन, मछली, फल, चावल, दाल तथा अन्य खाद्य सामग्री पर भी अवैध शुल्क लगाया जाता है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि असम से बाहर भेजी जाने वाली सूखी सुपारी (ड्राई एरिका नट) पर भी कथित रूप से प्रति किलोग्राम 60 रुपए तक की अवैध वसूली की जाती है।

मंत्री और बीटीसी प्रमुख पर लगाया आरोप

राइजर दल के नेता ने आरोप लगाया कि इस कथित सिंडिकेट को राज्य के कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल बरुवा तथा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के प्रमुख हाग्रामा मोहिलारी का संरक्षण प्राप्त है। समाचार लिखे जाने तक दोनों नेताओं की ओर से इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

दिल्ली से की तुलना

गोगोई ने कहा कि दिल्ली में अंडा लगभग रु. 6.50 में उपलब्ध है, जबकि असम में उपभोक्ताओं को लगभग 10 रुपए प्रति अंडा देना पड़ रहा है।

उनका कहना है कि यदि कथित अवैध वसूली समाप्त कर दी जाए तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक असम सरकार ने अखिल गोगोई द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था। यदि सरकार की ओर से प्रतिक्रिया या जांच संबंधी कोई घोषणा होती है, तो उससे पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

मिजोरम की लमसियाल गुफा का खुलने लगा रहस्य

जन जन विचार
...✍ आइजल

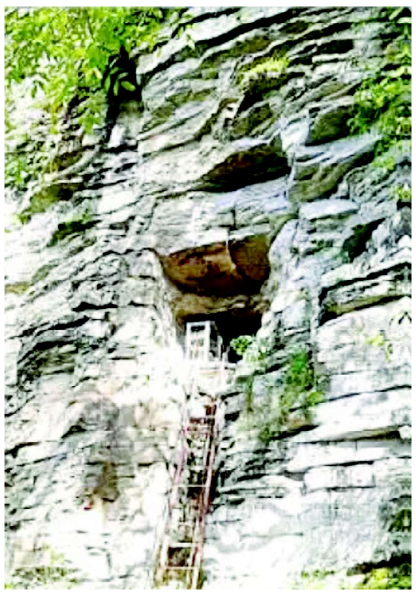

मिजोरम के चम्फाई जिले स्थित ऐतिहासिक लमसियाल पुक गुफा से प्राप्त मानव कंकालों की पहली वैज्ञानिक कार्बन-14 (रेडियोकार्बन) जांच ने पूर्वोत्तर के इतिहास और पुरातत्व अध्ययन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। जांच में एक मानव अस्थि नमूने की आयु 1729 से 1789 ईस्वी के बीच की पाई गई है। इससे पहली बार इस गुफा में मिले मानव अवशेषों के काल निर्धारण का वैज्ञानिक आधार सामने आया है।

हालांकि विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यह निष्कर्ष केवल एक नमूने पर आधारित है और गुफा में मौजूद अन्य कंकालों की आयु जानने के लिए अलग-अलग वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक होंगे।

अमेरिका की प्रयोगशाला में हुई जांच

मिजो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने गुफा से प्राप्त मानव अस्थि का एक नमूना अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बीटा एनालिटिक प्रयोगशाला को भेजा था।

विस्तृत रेडियोकार्बन विश्लेषण के बाद प्रयोगशाला ने नमूने की आयु 18वीं शताब्दी (1729-1789 ईस्वी) निर्धारित की।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिपोर्ट पूर्वोत्तर भारत के पुरातात्विक इतिहास को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केवल एक नमूने की हुई जांच

मिजो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने कहा है कि गुफा में बड़ी संख्या में मानव कंकाल और खोपड़ियां मौजूद हैं, लेकिन अभी केवल एक नमूने की ही कार्बन डेटिंग कराई गई है। इसलिए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि गुफा में मिले सभी मानव अवशेष इसी काल के हैं।

सोसाइटी ने बताया कि पूरे स्थल का सही इतिहास जानने के लिए आगे और अधिक कार्बन डेटिंग, डीएनए विश्लेषण तथा अन्य वैज्ञानिक परीक्षण कराए जाएंगे।

क्यों महत्वपूर्ण है लमसियाल पुक ?

चम्फाई जिले के फरकॉन गांव के निकट स्थित लमसियाल पुक को मिजोरम के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में माना जाता है। ऊंची चट्टानों पर स्थित यह गुफा लंबे समय से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है।

गुफा में बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिलने के कारण वर्षों से यह प्रश्न बना हुआ था कि ये लोग कौन थे, यहां कैसे पहुंचे और इनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई।

अब कार्बन डेटिंग ने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की दिशा में पहला वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराया है।

सरकार ने दिया आर्थिक सहयोग

मिजो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने बताया कि वर्ष 2023 में मिजोरम कला एवं संस्कृति विभाग ने कार्बन-14 परीक्षण के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी।

इसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में वैज्ञानिक परीक्षण कराया जा सका।

आगे क्या होगी जांच ?

विशेषज्ञों के अनुसार आगामी चरणों में- अन्य मानव अवशेषों की कार्बन डेटिंग, डीएनए परीक्षण, पुरातात्विक उत्खनन, ऐतिहासिक अभिलेखों का अध्ययन तथा गुफा के सांस्कृतिक और मानवशास्त्रीय महत्व का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा।

यदि आगे की जांच में अलग-अलग कालखंडों के मानव अवशेष मिलते हैं, तो यह स्थल पूर्वोत्तर भारत के इतिहास के लिए और भी महत्वपूर्ण बन सकता है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

हिंदी बनी असम...

जुलाई को वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुवा राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सरकार की वित्तीय योजनाओं और विकास संबंधी प्राथमिकताओं का खाका रखा जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत विधानसभा के आधिकारिक प्रसारण चैनल एएलए टीवी का नाम बदलकर असम विधानसभा टीवी किया जाएगा। इसे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की तर्ज पर आधुनिक स्वरूप देने की योजना है, ताकि आम नागरिक विधानसभा की कार्यवाही को अधिक प्रभावी ढंग से देख और समझ सकें।

इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा की आधिकारिक भाषाओं में से बोडो भाषा को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं का सम्मान करती है और हिंदी को शामिल करने का निर्णय केवल कार्यवाही को अधिक व्यापक और सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह निर्णय असम की बहुभाषी पहचान को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक सहभागी और जनोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

संपादकीय

इंग्लैंड में संघर्ष

भारतीय क्रिकेट से हर श्रृंखला में जीत की उम्मीद की जाती है। लेकिन हालिया घटनाक्रम ने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले आयरलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीम के खिलाफ टी-20 श्रृंखला गंवाना और उसके बाद इंग्लैंड दौरे के शुरुआती तीन मुकाबलों में जीत के लिए संघर्ष करना यह संकेत देता है कि भारतीय टीम के सामने केवल फॉर्म का नहीं, बल्कि रणनीति और संतुलन का भी संकट है।

टी-20 क्रिकेट में भारत की पहचान आक्रामक बल्लेबाजी रही है, लेकिन हाल के मैचों में शीर्ष क्रम की अस्थिरता और मध्यक्रम की नाकामी बार-बार सामने आई है। बड़े शॉट लगाने की जल्दबाजी में बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी भूलते दिखाई दिए। दूसरी ओर, गेंदबाजी में डेथ ओवरों की कमजोरी और फील्डिंग की साधारण गलतियों ने विपक्षी टीमों को अतिरिक्त मौके दिए।

सबसे बड़ा प्रश्न टीम चयन पर है। क्या चयन केवल नाम और प्रतिष्ठा के आधार पर हो रहा है, या वर्तमान प्रदर्शन को भी समान महत्व मिल रहा है? युवा खिलाड़ियों को अवसर देना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें स्पष्ट भूमिका और स्थिरता भी मिलनी चाहिए। लगातार प्रयोग टीम का आत्मविश्वास भी प्रभावित करते हैं।

भारतीय क्रिकेट के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और मजबूत बेंच स्ट्रेंथ दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है। लेकिन केवल प्रतिभा से जीत नहीं मिलती। अनुशासन, स्पष्ट रणनीति, सही टीम चयन और दबाव में बेहतर निर्णय ही बड़ी टीमों की पहचान होते हैं।

समय आ गया है कि भारतीय टीम बहानों की जगह आत्मविश्लेषण करे। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिले सबक यदि समय रहते नहीं सीखे गए, तो आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में इसकी कीमत और भारी पड़ सकती है। हार से सीखना ही महान टीमों की पहचान है। भारतीय क्रिकेट के सामने अब यही सबसे बड़ी चुनौती है।

यह कैसा विकसित भारत ?

जन जन विचार
...✍ नीरज कुमार दुबे

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गुरुग्राम जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र हर वर्ष मानसून आते ही जलभराव, जाम और अव्यवस्था की पहचान बन जाते हैं? क्या यह केवल मौसम की मार है, या फिर हमारी नगर योजना, निर्माण व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी की सबसे बड़ी असफलता है? यदि हर वर्ष यही स्थिति बननी है, तो फिर हर वर्ष होने वाली तैयारियों और बैठकों का परिणाम आखिर कहां दिखाई देता है?

क्या स्मार्ट सिटी का अर्थ केवल चौड़ी सड़कें, चमकदार भवन और आकर्षक परियोजनाएं हैं? क्या स्मार्ट शहर वह नहीं होना चाहिए जो सामान्य से अधिक बारिश को भी सहजता से संभाल सके? यदि अरबों रुपए जल निकासी, सड़क निर्माण और शहरी विकास पर खर्च हो रहे हैं, तो पहली तेज बारिश में ही सड़कें नदी और चौराहे तालाब क्यों बन जाते हैं?

क्या हर मानसून के बाद वही तस्वीरें, वही बयान और वही आश्वासन सुनना हमारी नियति बन चुकी है? क्या कभी किसी अधिकारी, किसी एजेंसी या किसी निर्माण करने वाली संस्था की जवाबदेही तय हुई? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं कि हर वर्ष खर्च होने वाला धन आखिर किस काम में लगाया जाता है?

क्या समस्या केवल अधिक बारिश की है, या फिर प्राकृतिक जलमार्गों पर अतिक्रमण, बिना योजना के विस्तार, कमजोर निर्माण और रखरखाव की अनदेखी इसकी असली वजह है? क्या नदियों, तालाबों और पुराने जल निकासी मार्गों को पाटकर खड़ी की गई इमारतों की कीमत अब पूरा समाज नहीं चुका रहा है? यदि शहरों की सांस लेने वाली प्राकृतिक व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाएगा, तो पानी आखिर जाएगा कहां?

क्या यह सामान्य बात मानी जा सकती है कि बारिश होते ही एंबुलेंस फंस जाए, बच्चे स्कूल न पहुंच सकें, कर्मचारी दफ्तर न जा सकें, बाजार ठप हो जाएं, रेल और हवाई यात्रा थम जाएं और सामान्य जीवन रुक जाए? क्या हर वर्ष होने वाले आर्थिक नुकसान, समय की बर्बादी और जनजीवन की परेशानी का कोई हिसाब भी रखा जाता है? यदि रखा जाता है, तो फिर समाधान आज तक क्यों नहीं मिला?

क्या विकसित भारत केवल बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे और गगनचुंबी इमारतों से बनेगा? या फिर उसकी पहचान ऐसी मजबूत बुनियादी व्यवस्था से होगी जो हर मौसम में नागरिकों को सुरक्षित और सुगम जीवन दे सके? क्या विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना उन शहरों के सहारे पूरा होगा जो हर मानसून में ठहर जाते हैं?

क्या केवल सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाना पर्याप्त है? क्या नागरिकों की भी जिम्मेदारी नहीं कि वे नालों में कचरा न डालें, जलमार्गों पर अतिक्रमण का विरोध करें और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं? लेकिन क्या यह भी उतना ही सच नहीं कि व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी पर होती है जिसके हाथ में योजना, संसाधन और निर्णय की शक्ति होती है?

देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम 2047 के विकसित भारत की इमारत उस बुनियाद पर खड़ी कर रहे हैं जो हर मानसून में हिल जाती है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि विकास के दावों से पहले शहरों की जल निकासी व्यवस्था, निर्माण की गुणवत्ता, नगर नियोजन और प्रशासनिक जवाबदेही को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए? क्या जनता को हर वर्ष एक ही परेशानी झेलने के लिए मजबूर रखना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान हो सकती है? और यदि इन सवालों का उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या हमें पहले विकसित भारत का सपना देखना चाहिए, या पहले उसकी मजबूत बुनियाद तैयार करनी चाहिए?

क्या हम 2047 के विकसित भारत की इमारत उस बुनियाद पर खड़ी कर रहे हैं जो हर मानसून में हिल जाती है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि विकास के दावों से पहले शहरों की जल निकासी व्यवस्था, निर्माण की गुणवत्ता, नगर नियोजन और प्रशासनिक जवाबदेही को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए?

हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं। हम आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट शहरों और वैश्विक स्तर की सुविधाओं का दावा कर रहे हैं।

बिहार में बदलाव : जाति-धर्म तोड़ न्याय के लिए एक हुआ समाज

जन जन विचार
...✍ उमेश चतुर्वेदी

बिहार में जातिवादी राजनीति के गढ़ भोजपुर में सवर्ण युवक भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हत्या ने अप्रत्याशित सामाजिक बदलाव को उजागर किया है। दलित और पिछड़े समुदाय भी न्याय के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जो राज्य में पारंपरिक जातिगत दीवारों को तोड़ते हुए एक नए सामाजिक सद्भाव का संकेत है। यह जनाक्रोश बिहार की राजनीति और सामाजिक सोच के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

जाति और धर्म के बिना आज राजनीति की कल्पना बेमानी है, लेकिन बिहार में जातिवाद का असर कुछ ज्यादा ही दिखता है। यहां मानस किस कदर जातिवाद के घेरे में है, इसे समझने के लिए किसी खास जाति के अपराधियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को देखना होगा। तब उस अपराधी के जाति विशेष द्वारा उसे बेकसूर बताने और कार्रवाई को जातिवादी बदला बताने की होड़ लग जाती है। लेकिन इसी बिहार में हाल ही में हुई एक घटना की प्रतिक्रिया में उभरा जनाक्रोश इसके ठीक उलट है। इसमें जाति और धर्म की सीमाएं टूट गई हैं। भोजपुर पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए सवर्ण युवक भरत तिवारी के इंसाफ के लिए उतरे लोगों के बीच कोई जातीय दीवार नजर नहीं आ रही। हालांकि इसे भी जातीय रंग देने की कोशिश की गई, तो उसके खिलाफ उसी दलित समाज के स्त्री और पुरुष मैदान में उतर आए, जिनकी रहनुमाई का दावा करने वाली राजनीति हस्ती ने यह रंग देने का प्रयास किया था।

इससे इनकार नहीं कि भारतीय समाज में ऊंच-नीच का भाव रहा है। फिर भी समाज में सद्भाव, सहयोग और मेलजोल की गहरी परंपरा है। सामाजिक मामलों में कई बार जाति की दीवारें टूटती भी नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव और राजनीति का मसला सामने आता है, जातीय सोच पूरी ताकत से उभर आती है। बिहार इस मामले में कुछ ज्यादा ही बदनाम है। ऐसे माहौल में अगर सवर्ण समुदाय के भरत तिवारी की पुलिस के हाथों हुई हत्या के खिलाफ सड़कों पर दलित और पिछड़े समुदाय तक के लोग उतर आएं तो मानना पड़ेगा कि पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था का जीन अब भी देश की रगों में बह रहा है। बस उसे जगाने की जरूरत है। हालांकि भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ को भी जातीय रंग देने की कोशिश भी हुई। हैरत की बात है कि इसके पीछे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नजर आए। जातिवादी चश्मे से इस घटना को देखते हुए उन्होंने कह दिया कि भरत तिवारी चूंकि ब्राह्मण था, इसीलिए सवर्ण समाज आक्रोशित है। उसकी जगह कोई दलित और पिछड़ा होता तो इस मामले को इतना तूल नहीं दिया जाता। मांझी के इस बयान ने जातिवादी खोल से बाहर निकले जनाक्रोश की आग में घी का काम किया। विरोध में भरत के गांव बिलौटी ही नहीं, आसपड़ोस के दलित और पिछड़े परिवार भी गुस्से से भर उठे। गंगा के कटान से प्रभावित ये लोग मांझी की लानत-मलामत में उतर आए। उन्होंने उलटे मांझी से ही पूछ लिया कि हमारे नेता होने के बावजूद उन्होंने उनकी हालत जानने की कोशिश क्यों नहीं की। लोगों का कहा था कि जिसके खिलाफ वे बोल रहे हैं, साधनहीन होने की बजाय वही व्यक्ति उनके साथ खड़ा रहा।

धन दिशा

500 की एसआईपी और देरी की कीमत

पिछले अंक में हमने एसआईपी की बुनियादी बात की-कि यह कैसे काम करता है, और जल्दी शुरू करना क्यों जरूरी है। इस हफ्ते, आइए असली आंकड़ों में देखें कि एक छोटी-सी एसआईपी वाकई कितना बड़ा रूप ले सकती है-और शुरुआत में की गई देरी असल में कितना भारी पड़ती है।

एसआईपी है क्या

एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान - हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में अपने आप निवेश होना, जैसे कोई मासिक किस्त। न बाजार का समय देखने की जरूरत, न एक साथ बड़ी रकम जोड़ने का इंतजार। आप जिस फंड में पैसा लगाते हैं, वही फंड कई कंपनियों के शेयर या बॉन्ड में निवेश करता है, और उसकी वैल्यू बाजार के साथ ऊपर-नीचे होती रहती है - लंबे समय में यह उतार-चढ़ाव औसतन एक अच्छी बढ़त में बदल जाता है।

500 रुपए महीना - सच में कितना बनता है?

मानते हैं कि एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में औसतन 12 प्रतिशत सालाना बढ़त मिलती है (यह कोई गारंटी नहीं, बस एक सामान्य अनुमान है, जो इक्विटी फंड के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है)। अगर आप सिर्फ 500 रुपए महीना यानी रोज का लगभग 17 रुपए-एक एसआईपी में डालना शुरू करें, तो देखिए समय के साथ यह रकम कैसे बढ़ती है-

समय	कुल जमा रकम	अनुमानित वैल्यू
5 वर्ष	रु. 30,000	लगभग रु. 41,000
10 वर्ष	रु.60,000	लगभग रु.1.16 लाख
15 वर्ष	रु.90,000	लगभग रु.2.52 लाख
20 वर्ष	रु.1.2 लाख	लगभग रु.5 लाख
25 वर्ष	रु.1.5 लाख	लगभग रु.9.5 लाख
30 वर्ष	रु.1.8 लाख	लगभग रु.17.6 लाख

20 साल में, सिर्फ रु.500 महीने की एसआईपी से आपने कुल रु.1.2 लाख जमा किए, लेकिन फंड की वैल्यू लगभग रु. 5 लाख तक पहुंच सकती है - फर्क सिर्फ समय और नियमितता का है।

ध्यान दीजिए - पहले 10 साल में बढ़त धीमी लगती है, लेकिन आखिरी 10 साल में यह तेजी से ऊपर जाती है। यही कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि) की ताकत है - पुराना मुनाफा भी अपने आप मुनाफा कमाने लगता है। इसलिए जितनी जल्दी शुरुआत करें, उतना अच्छा।

देरी की कीमत - एक उदाहरण से समझें

मान लीजिए किसी का लक्ष्य है 55 साल की उम्र तक एक तय रकम जोड़ना। अगर वह 25 साल की उम्र से रु. 2,000 महीना एसआईपी शुरू करता है, तो 30 साल में 12 प्रतिशत की दर पर, यह रकम बढ़कर लगभग रु.70 लाख हो सकती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति शुरुआत 5, 10 या 15 साल टाल दे, तो उसी रु.70 लाख के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर महीने कितना ज्यादा निवेश करना होगा, यह नीचे देखें-

शुरुआत कब करें	मासिक एसआईपी	नतीजा
अभी से (30 वर्ष)	रु.2,000	रु.70 लाख तक
5 वर्ष बाद (25 वर्ष)	रु.3,700	रु.70 लाख तक
10 वर्ष बाद (20 वर्ष)	रु.7,000	रु.70 लाख तक
15 वर्ष बाद (15 वर्ष)	रु.14,000	रु.70 लाख तक

मतलब साफ है,10 साल की देरी से आपको लगभग दोगुनी रकम महीने में डालनी पड़ती है, सिर्फ उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। यही 'देरी की कीमत' है और यह किसी बैंक के पेनाल्टी जैसा नहीं दिखता, फिर भी यह आपकी जेब से असल में निकल जाता है।

अगले हफ्ते : टर्म इंश्योरेंस - आपके परिवार की सुरक्षा का सबसे जरूरी और सबसे सस्ता तरीका।

इस कॉलम के लिए आपका कोई सवाल है? हमें भेजिए-

-कोमल जैन

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, संस्थापक, वेल्थप्लायर्स- मो. 9004510577

ई 20 पेट्रोल पर सरकार का बचाव

इंजन को नुकसान का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं

जन जन विचार ...✍ नई दिल्ली

पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (ई20) को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच केंद्र सरकार ने पहली बार विस्तृत रूप से अपना पक्ष रखा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई20 पेट्रोल किसी जल्दबाजी का फैसला नहीं, बल्कि वर्षों की वैज्ञानिक जांच, चरणबद्ध परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित कार्यक्रम है। सरकार का दावा है कि अब तक हुए परीक्षणों में इससे वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है।

हालांकि, इस बयान से कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ई20 कार्यक्रम अभी भी एक 'प्रयोगात्मक चरण' में है और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का पूरा आकलन अगले वर्ष तक ही संभव होगा। ऐसे में सरकार के दो अलग-अलग रुखों ने इस मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है।

दिल्ली में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से पूर्व इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि वर्ष 2013-14 में पेट्रोल में केवल 1.5 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता था। इसके बाद व्यापक अनुसंधान, परीक्षण और चरणबद्ध विस्तार के बाद देश ने दिसंबर 2025 तक 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया।

प्रेस वार्ता में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हुंडई इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सभी कंपनियों का कहना था कि व्यापक परीक्षणों के दौरान ई20 ईंधन से इंजन को गंभीर नुकसान या प्रदर्शन में किसी असामान्य गिरावट के प्रमाण नहीं मिले हैं।

मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारी राहुल भारती ने माना कि वर्ष 2023 से पहले निर्मित पेट्रोल वाहनों को लेकर उपभोक्ताओं में चिंता स्वाभाविक है, लेकिन कंपनी की जांच में ई20 ईंधन को लेकर कोई गंभीर तकनीकी समस्या सामने नहीं आई।

सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटती है और किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है। पूर्व इंडियन ऑयल चेयरमैन बी. अशोक ने भी दावा किया कि वैज्ञानिक अध्ययनों में इंजन को नुकसान या माइलेज में बड़ी गिरावट के प्रमाण नहीं मिले हैं।

दूसरी ओर, देश के कई वाहन मालिकों का कहना है कि विशेषकर पुराने मॉडलों में ई20 के कारण माइलेज घटा है, रखरखाव का खर्च बढ़ा है और इंजन के कुछ हिस्सों के जल्दी खराब होने की शिकायतें सामने आई हैं।

सरकार का कहना है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सियाम जैसी संस्थाओं ने इस ईंधन की व्यापक जांच की है और यह बीएस-VI उत्सर्जन मानकों के अनुरूप है। सरकार का दावा है कि एथेनॉल मिश्रण विश्व के कई देशों में पहले से सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है और भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब निगाहें अगले वर्ष आने वाले उन विस्तृत आंकड़ों पर टिकी हैं, जिनसे यह स्पष्ट होगा कि ई20 ईंधन के दीर्घकालिक प्रभाव वास्तव में कितने सुरक्षित और लाभकारी साबित होते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर अब नरमी नहीं

बारुईपुर से श्रीगंगानगर तक त्वरित कार्रवाई ने दिया स्पष्ट संदेश

जन जन विचार ...✍ नई दिल्ली

देश एक बार फिर दो जघन्य घटनाओं से स्तब्ध है। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या और राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। इन घटनाओं ने न केवल महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की जनता की अपेक्षा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

बारुईपुर मामले में पुलिस ने विशेष जांच दल गठित कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौत ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया, लेकिन इस घटनाक्रम ने अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की सक्रियता को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया। राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि प्रारंभिक स्तर पर किसी प्रकार की पुलिस लापरवाही सिद्ध होती है तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।

उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अनेक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच लगातार आगे बढ़ रही है तथा फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने केवल आरोपियों तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि सोशल मीडिया पर पीड़िता के नाम से फैलाई जा रही भ्रामक तस्वीरों और अफवाहों पर भी सख्ती दिखाई है। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि अपराध के साथ-साथ दुष्प्रचार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इन दोनों घटनाओं ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर सामने रखा है-क्या केवल कठोर दंड ही पर्याप्त है? विशेषज्ञों का मानना है कि कानून का भय आवश्यक है, लेकिन इसके साथ सामाजिक जागरूकता, बच्चों की सुरक्षा शिक्षा, त्वरित न्याय व्यवस्था, प्रभावी पुलिसिंग और परिवार व विद्यालय की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

देश में महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध अपराध केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना की भी परीक्षा है। अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी पीड़ितों के साथ अन्याय होगी।

क्या यूपीएससी ही है करियर का बेहतर विकल्प ?

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में गिनी जाती है। हर वर्ष लाखों युवा आईएएस, आईपीएस और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में चयन का सपना लेकर परीक्षा में शामिल होते हैं। हालांकि, सफलता का प्रतिशत बेहद कम होने के कारण विशेषज्ञ उम्मीदवारों को तैयारी के साथ-साथ वैकल्पिक करियर विकल्पों पर भी ध्यान देने की सलाह देते हैं।

एक प्रतिशत से भी कम को मिलती है अंतिम सफलता

हर साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए लगभग 10 से 13 लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं। इनमें से करीब 5 से 6 लाख अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के बाद लगभग 12 से 15 हजार उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होते हैं, जबकि अंतत: करीब 900 से 1,100 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न सेवाओं के लिए होता है।

इस प्रकार, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों में एक प्रतिशत से भी कम अभ्यर्थी अंतिम चयन तक पहुंच पाते हैं।

कब लें वैकल्पिक करियर पर विचार ?

विशेषज्ञों के अनुसार यदि अभ्यर्थी की तैयारी में लगातार सुधार हो रहा है और वह प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा जैसे चरणों तक पहुंच रहा है, तो तैयारी जारी रखी जा सकती है। लेकिन यदि कई प्रयासों के बावजूद लगातार असफलता मिल रही हो, तो समय रहते अन्य करियर विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

तैयारी के दौरान विकसित करें अतिरिक्त कौशल

यूपीएससी की तैयारी से अनुशासन, विश्लेषण क्षमता, लेखन कौशल और समसामयिक विषयों की समझ मजबूत होती है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए अन्य व्यावसायिक कौशल भी विकसित करने चाहिए, जैसे-

डिजिटल टूल्स का उपयोग, डेटा एनालिटिक्स, कंटेंट राइटिंग, प्रोजेक्ट एवं मैनेजमेंट स्किल्स, संचार एवं प्रस्तुतीकरण कौशल।

केवल यूपीएससी ही नहीं अन्य अवसर भी हैं

करियर विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अवसर तलाशने चाहिए। निजी क्षेत्र, शोध, शिक्षा, नीति विश्लेषण, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट प्रबंधन और डिजिटल उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी बेहतर करियर की संभावनाएं उपलब्ध हैं। यूपीएससी निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित करियर विकल्प है, लेकिन इसे सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं माना जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के साथ-साथ वैकल्पिक कौशल और करियर विकल्पों पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में रोजगार और करियर विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।

आरआरसी, प्रयागराज में एक्ट अप्रेंटिस के 1853 पदों पर भर्ती

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी), प्रयागराज ने एक्ट अप्रेंटिस के 1853 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 8 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। रेलवे में प्रशिक्षण प्राप्त कर करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

आयु सीमा

7 जुलाई 2026 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

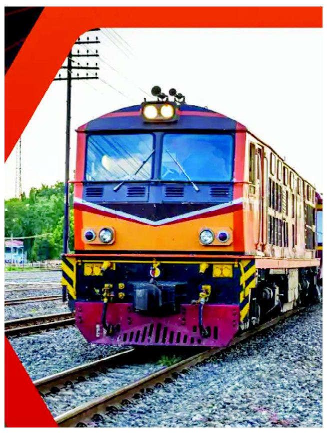

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग : 100 रुपए

एससी, एसटी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी : नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा। अभ्यर्थियों का चयन 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के बाद एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू : 8 जुलाई 2026

अंतिम तिथि : 8 अगस्त 2026

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

टैटू बन सकता है सरकारी नौकरी में रुकावट ?

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

युवाओं में टैटू बनवाने का चलन तेजी से बढ़ा है। कोई अपनी कलाई पर धार्मिक प्रतीक बनवाता है, तो कोई हाथ या गर्दन पर नाम या डिजाइन। लेकिन जब सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू होती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है-क्या टैटू सरकारी नौकरी में रुकावट बन सकता है?

इसका जवाब 'हां' या 'नहीं' में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर सरकारी विभाग के नियम अलग-अलग हैं। कुछ नौकरियों में टैटू से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कुछ वर्दीधारी सेवाओं में इसे लेकर सख्त मानदंड लागू हैं।

सिविल सेवाओं में टैटू से नहीं होती परेशानी

अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस), एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो सामान्य तौर पर टैटू बाधा नहीं बनता।

हालांकि, टैटू ऐसा नहीं होना चाहिए जो- अश्लील या आपत्तिजनक हो। किसी धर्म, जाति या समुदाय के प्रति नफरत फैलाता हो। देश विरोधी या हिंसा को बढ़ावा देने वाला संदेश देता हो।

ऐसे मामलों में उम्मीदवार की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

पुलिस और अर्धसैनिक बलों में नियम अलग

राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में टैटू को लेकर नियम अपेक्षाकृत सख्त होते हैं।

आमतौर पर, शरीर के दिखाई देने वाले हिस्सों पर बड़े या भड़कीले टैटू स्वीकार नहीं किए जाते।

धार्मिक या पारंपरिक प्रतीकों को कुछ परिस्थितियों में अनुमति मिल सकती है।

अंतिम निर्णय संबंधित भर्ती के मेडिकल बोर्ड और अधिसूचना के नियमों के आधार पर लिया जाता है।

इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें।

सेना में टैटू पर सबसे सख्त नीति

भारतीय सेना में टैटू को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं। सामान्यत:

-पूरे शरीर पर बड़े टैटू स्वीकार नहीं किए जाते।

-कुछ विशेष पारंपरिक या जनजातीय समुदायों के उम्मीदवारों को निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिल सकती है।

अन्य उम्मीदवारों के लिए केवल सीमित स्थानों पर और निर्धारित नियमों के अनुसार टैटू की अनुमति होती है।

इसी तरह नौसेना और वायुसेना में भी मेडिकल मानकों के तहत टैटू की जांच की जाती है।

क्या टैटू हटाने के बाद नौकरी मिल सकती है ?

अगर किसी भर्ती में टैटू नियमों के अनुरूप नहीं है, तो कई उम्मीदवार लेजर से उसे हटवा लेते हैं।

ध्यान रखने योग्य बातें-टैटू हटाने के बाद भी उसके निशान रह सकते हैं। मेडिकल बोर्ड यह जांचता है कि त्वचा की स्थिति भर्ती मानकों के अनुरूप है या नहीं। केवल टैटू हटा देना अपने आप चयन की गारंटी नहीं देता।

टैटू बनवाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

अगर भविष्य में सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, तो टैटू बनवाने से पहले संबंधित भर्ती के नियम जरूर पढ़ें। बड़े, दिखने वाले और विवादित टैटू से बचें। धार्मिक या पारंपरिक टैटू भी बनवाने से पहले उसकी अनुमति संबंधी नियमों की जानकारी लें। भर्ती प्रक्रिया के दौरान टैटू की जानकारी छिपाने की कोशिश न करें, क्योंकि मेडिकल परीक्षण में इसका पता चल सकता है। सरकारी नौकरी में टैटू होना हमेशा बाधा नहीं बनता। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अधिकांश प्रशासनिक सेवाओं में सामान्य टैटू से आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती। वहीं पुलिस, सीआरपीएफ और विशेष रूप से भारतीय सेना में टैटू को लेकर अलग और अपेक्षाकृत कड़े नियम लागू होते हैं।

जिम्बाब्वे दौरे के लिए युवा भारत तैयार

टी20 टीम घोषित : संजू बाहर, रिंकू की वापसी; वैभव सूर्यवंशी पर फिर भरोसा

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान बनाए गए हैं। चयन समिति ने इस दौरे के लिए युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए कई नए चेहरों को मौका दिया है। सबसे बड़ी चर्चा विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम से बाहर रखने और रिंकू सिंह की वापसी को लेकर है।

लगातार तीसरी टी20 श्रृंखला के लिए युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में बनाए रखा गया है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के बाद अब जिम्बाब्वे दौरे पर भी उन्हें मौका मिला है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि चयनकर्ता उन्हें भविष्य के खिलाड़ी के रूप में तैयार करना चाहते हैं। पंजाब किंग्स के प्रभसिमरन सिंह को भी टीम में जगह मिली है, जबकि ईशान किशन दूसरे विकेटकीपर होंगे।

जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)

चयनकर्ताओं ने कार्यभार प्रबंधन (वर्कलोड मैनेजमेंट) को ध्यान में रखते हुए कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और मयंक यादव को मौका दिया गया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी विश्राम दिया गया है। इसके अलावा सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे और वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल कर युवा और संतुलित संयोजन तैयार किया गया है।

बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला के लिए भी संशोधित टीम घोषित की है। चोट के कारण नीतीश कुमार रेड्डी टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह ऑलराउंडर शिवम दुबे को शामिल किया गया है। चयनकर्ताओं को उम्मीद थी कि नीतीश फिट होकर वापसी करेंगे, लेकिन समय पर पूरी तरह स्वस्थ नहीं होने के कारण उन्हें बाहर रखना पड़ा।

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीनों टी20 मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे। पहला मैच 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और तीसरा 26 जुलाई को होगा। युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम से एक बार फिर दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 4 जुलाई 2026 का दिन एक नए स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। मात्र 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पदार्पण कर भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

वैभव ने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में निडर बल्लेबाजी का परिचय देते हुए मात्र 10 गेंदों में 14 रन बनाए। उनकी छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी में दो शानदार छक्के शामिल रहे। एक छक्का उन्होंने दुनिया के तेज गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर की गेंद पर लगाया, जबकि दूसरा जोश टंग के खिलाफ जड़ा। बाद में विल जैक्स ने उन्हें स्टंप आउट कर पवेलियन भेजा।

वैभव का यह सफर आईपीएल 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद और तेज हो गया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने 776 रन बनाए और 237.31 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से पूरे टूर्नामेंट में धूम मचाई। उन्होंने एक शतक भी लगाया और पूरे सीजन में पांच पुरस्कार अपने नाम किए। इसी प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय टीम का दरवाजा खोल दिया।

एलवियान बरदलै राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित

रोहा। रोहा के बौद्धिधर्मा कराटे क्लब के खिलाड़ी एवं रोहा शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन के कक्षा 10 के छात्र एलवियान बरदलै ने चराईदेउ जिले के बरपात्र में 1 से 3 जुलाई तक आयोजित विद्या भारती नॉर्थ ईस्ट स्कूल गेम्स चयन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र, विद्यालय और क्लब का नाम रोशन किया है।

श्री-डान ब्लैक बेल्ट प्रशिक्षक नित्य कुमार पातर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एलवियान का चयन अब 27 नवंबर को मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाले विद्या भारती नेशनल गेम्स के लिए हुआ है। प्रशिक्षक पातर ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर एलवियान को दिसंबर में आयोजित होने वाले विद्या भारती नेशनल स्कूल गेम्स में भी भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

वर्ष 2017 में स्थापित बौद्धिधर्मा कराटे क्लब आत्मरक्षा एवं शारीरिक-मानसिक विकास के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। क्लब के 20 विद्यार्थी ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर चुके हैं तथा राज्य एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में कई पदक जीत चुके हैं।

एलवियान की इस उपलब्धि पर क्लब के सदस्यों, अभिभावकों और विद्यार्थियों में हर्ष का माहौल है। क्लब की ओर से उन्हें पारंपरिक फूलाम गामोछा पहनाकर सम्मानित किया गया और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

चढ़ावा चोरी : आस्था,...

प्रशासनिक निगरानी पर भी प्रश्न उठाए गए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने में कमी रही। इसी संदर्भ में ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों की प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी चर्चा शुरू हुई।

हालांकि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

मुख्यमंत्री योगी का रुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ व्यक्तियों की कथित हरकतों के आधार पर पूरे ट्रस्ट या अयोध्या की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं है।

संत समाज भी आया सामने

अयोध्या के अनेक संतों और धार्मिक नेताओं ने अपील की है कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

उनका कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से कार्य करने दिया जाना चाहिए।

विपक्ष के आरोप

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा अन्य विपक्षी दलों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि यदि सुरक्षा व्यवस्था समय पर मजबूत होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कुछ नेताओं ने चढ़ावे के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

सत्तापक्ष का जवाब

भाजपा का कहना है कि सरकार ने शिकायत मिलते ही एसआईटी गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को छिपाने का प्रयास नहीं किया गया।

पार्टी नेताओं का कहना है कि दोषियों को कानून के अनुसार दंड मिलेगा, लेकिन बिना अंतिम जांच रिपोर्ट के पूरे ट्रस्ट या मंदिर व्यवस्था पर आरोप लगाना उचित नहीं है।

गोरखपुर का रामगढ़ताल बना पूर्वांचल का 'मरीन ड्राइव'

जन जन विचार
...गोरखपुर

उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है-राप्ती, जो गोरखपुर से होकर बहती है। इसी नदी के किनारे एक गांव बसा था-रामग्राम। कहते हैं कि एक बार राप्ती में भयंकर बाढ़ आई और इसने पूरा रामग्राम को बहा दिया। बाद में वहां विशाल ताल बन गया। तभी से इसे रामगढ़ताल कहा जाने लगा। अंग्रेजों के समय में रामगढ़ताल से होकर गोरखपुर के पुराने बाजार साहेबगंज तक नाव से कारोबार हुआ करता था। बाद में अंग्रेजों ने राप्ती नदी पर बांध बनवा दिया तो यह ताल हमेशा के लिए ताल बनकर रह गया। आज यही विशाल रामगढ़ताल पूरे गोरखपुर की शान बना हुआ है। लोग वहां नौका विहार करने, घूमने और रामगढ़ताल की हवा खाने जाते हैं।

'गोखुर झील' के रूप में रामगढ़ ताल

आधुनिक भू-शोध रामगढ़ ताल की कहानी को एक नया वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। रामगढ़ ताल राप्ती नदी की 'छाड़न झील' है। यानी नदी द्वारा छोड़े गए पुराने मार्गों में बना विशाल जल भंडार।

शहरनामा गोरखपुर में भूगोलविद प्रो. शिवशंकर वर्मा ने लिखा है-राप्ती नदी अपने अनिश्चित मार्ग परिवर्तन के कारण मशहूर रही है। भूगर्भीय सर्वेक्षण, उपग्रहीय आकलन और गोरखपुर के पुराने जलमार्गों जैसे गोड़धोइया नाला, बौलिया नाला, रेलवे गोल्फ ग्राउंड नाला की क्रमबद्धता से सिद्ध होता है कि कभी राप्ती नदी गोरखनाथ मंदिर के पास से बहती थी। समय के साथ नदी पश्चिम की ओर सरकती गई और उसके पुराने मार्गों में पानी भर जाने से कई छाड़न झीलें बनीं। इन्हीं में सबसे बड़ी झील बनी- रामगढ़ ताल।

ऋषि के श्राप ने बना दिया ताल

'गोरखपुर का इतिहास' जैसी किताबें लिखने वाले डॉ. दानपाल सिंह बताते हैं कि ऐसी जनश्रुतियां हैं कि रामगढ़ताल कभी विशाल नगर था। प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र में एक संपन्न राज्य था, जिसकी राजधानी 'जनकीर्ण' नाम के कस्बे में थी। कहते हैं कि यहां एक दिन एक ऋषि पधारे। राजा ने उनका आदर नहीं किया, जिससे वह क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने पूरे राज्य को श्राप दे दिया। नतीजा यह हुआ कि राजधानी समेत पूरा राज्य धंसता चला गया और बाद में जलभराव होने से यह रामगढ़ ताल बन गया।

रामगढ़ताल शुरुआती समय में 6 मील लंबा और 3 मील चौड़ा तालाब था। इसका दायरा करीब 18 वर्ग किलोमीटर था। मगर, अतिक्रमण के चलते आज यह करीब 7 वर्ग किलोमीटर में रह गया है।

राजा के अहंकार के चलते बन गया रामगढ़ताल

इतिहासकार दानपाल सिंह बताते हैं कि यहां रहने वाले बूढ़े-बुजुर्ग रामगढ़ ताल के बनने के पीछे की जो कहानी बताते हैं, वह उन लोगों ने अपने पूर्वजों से सुनी है। वह कहते हैं कि जिस स्थान पर रामगढ़ ताल बना है, वह गांव की घनी आबादी का हिस्सा था। यह एक राजा के अहंकार के चलते धंसना शुरू हो गया था। इस गढ़ से बचकर केवल बिल्ली ही भाग पाई थी। बाकी जो लोग भी थे, उस ताल में ही समा गए। आज भी यहां पर उस ताल के बीच में बड़े-बड़े कुएं हैं।

रामगढ़ताल का इतिहास

गोरखपुर के इतिहासकार डॉ. दानपाल सिंह बताते हैं कि रामगढ़ताल छठी सदी में नागवंशी कोलिय गणराज्य की राजधानी थी। यह वही वंश था, जहां से गौतम बुद्ध की माता और उनकी पत्नी आई थीं। प्राचीन काल में गोरखपुर का नाम भी रामग्राम ही था। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धातु अवशेषों पर बने स्तूपों को तोड़ कर उसमे स्थित धातु अवशेषों पर 84,000 स्तूप बनवाया था।

वह राम ग्राम के अंगार स्तूप को भी तोड़कर वहां से बुद्ध के धातु अवशेष निकालना चाहता था, मगर नागों के प्रबल प्रतिरोध के कारण वह यहां सफल नहीं हो सका। आखिरकार उसने सात स्तूपों से बुद्ध के धातु अवशेषों को निकलवा कर उसने 84,000 स्तूप बनवाए।

गोरखपुर का रामगढ़ताल छठी सदी में नागवंशी कोलिय गणराज्य की राजधानी थी। यह महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक से भी जुड़ा हुआ है। राप्ती नदी के अपनी धारा मोड़ने की वजह से यहां इतना बड़ा तालाब बन गया। यह ताल अपने भीतर इतिहास-भूगोल सब समेटे हुए है।

पूर्वांचल का मरीन ड्राइव बन चुका है रामगढ़ताल

रामगढ़ ताल आज 'पूर्वांचल के मरीन ड्राइव' के रूप में विकसित हो चुका है। ताल के किनारे बनी आकर्षक सड़कें, नौकायन सुविधाएं, वाटर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, लेजर शो और खूबसूरत सेल्फी पाइंट्स इसे आधुनिक पर्यटन केंद्र का रूप देते हैं। रेस्टोरेंट्स और मनोरंजन सुविधाओं से युक्त यह जगह युवाओं, परिवारों और पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गई है।

बरतें सावधानी : आप अपने या परिवार के किसी सदस्य को रामगढ़ताल के प्रतिबंधित क्षेत्र में न जानें दें। नौकायन कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप या आपके परिवार के सदस्य लाइफ जैकेट पहने हैं या नहीं। सेल्फी किसी खतरनाक जगह या गहरे पानी वाली जगह पर जाकर न लें और रेलिंग के उस पार न जाएं।

पर्यटकों की सुरक्षा की पुलिस की कार्ययोजना

पुलिस ने रामगढ़ताल के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। नई व्यवस्था के तहत हर एक किलोमीटर पर स्थायी रूप से दो-दो पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। साथ ही पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।

पीआरवी वाहनों की संख्या अब चार कर दी जाएगी। जल पुलिस चौकी भी खोलने की तैयारी है। इसके लिए स्थान चिह्नित कर पुलिस अधिकारी ने जीडीए को पत्र लिखा है।

पुलिस की कार्ययोजना में दो मार्गों की पहचान की गई है। इसमें पैडलेगंज से नौकायन तक ढाई किमी मार्ग पर रामगढ़ताल थाना से और आरकेबीके से पैडलेगंज तक ढाई किमी मार्ग पर कैंट थाने से हर एक किमी पर पुलिसकर्मियों की तैनाती सुबह से देर शाम तक की जाएगी।

ये ड्यूटी के दौरान एक किमी परिधि में गश्त करते रहेंगे और देखेंगे कि कोई भी पर्यटक रेलिंग पार करके ताल के पास सेल्फी लेने न जा पाए।

जल पुलिस चौकी खोलकर वहां पर कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जो किसी भी दुर्घटना पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।

২০০ মোবাইল আৰক্ষী থানা, গুৱাহাটীত ছেটেলাইট চিটি

ৰাজ্য কেবিনেটৰ একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

আসন্ন বিধানসভা অধিৱেশনৰ পূৰ্বে ৰাজ্য কেবিনেটে একাধিক নীতিগত আৰু জনস্বাৰ্থমূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি প্ৰশাসন, আইন-শৃংখলা, উদ্যোগ, পৰ্যটন আৰু নগৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত এই সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা কৰে।

২০০খন মোবাইল আৰক্ষী থানা গঠন

আইন-শৃংখলা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যজুৰি ২০০খন মোবাইল আৰক্ষী থানা স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰতিখন মোবাইল থানাত এখন বিশেষ বাহন আৰু উপ-পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া থাকিব।

১১২ নম্বৰত অভিযোগ ঘৰতে আৰক্ষী সেৱা

দেৰগাঁৱত এটা আধুনিক কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰি ৰবচ জৰুৰী সেৱা অধিক ফলপ্ৰসূ কৰা হ'ব। নাগৰিকে চচ্ছ ঘণ্টাই এই নম্বৰত ফোন কৰি অপৰাধ বা জৰুৰী ঘটনাৰ অভিযোগ দিব পাৰিব। অভিযোগ পোৱাৰ লগে লগে সংশ্লিষ্ট মোবাইল আৰক্ষী থানাই ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।

গুৱাহাটীত গঢ়ি উঠিব ছেটেলাইট চিটি

দ্ৰুত নগৰায়ণৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে গুৱাহাটী ছেটেলাইট চিটি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে Satellite City Development Authority গঠন কৰি সমগ্ৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব।

পৰ্যটন খণ্ডত নতুন নীতি

অসম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন শ্চসংশোধনীগ্ন বিধেয়ক বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব।নতুন আইনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ সকলো হোটেল, ৰিজৰ্ট আৰু হোমষ্টে বাধ্যতামূলকভাৱে পদ্ৰঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, যাৰ ফলত পৰ্যটন খণ্ড অধিক সংগঠিত হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে।

আমুলক ৩৩ বিঘা ভূমি আৱণ্টন

দুগ্ধ উৎপাদন আৰু দুগ্ধ উদ্যোগৰ বিকাশৰ লক্ষ্যৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আমুলক ৩৩ বিঘা ভূমি আৱণ্টনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চৰকাৰে ইয়াক কৃষক আৰু দুগ্ধ উৎপাদকসকলৰ বাবে লাভজনক পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰিছে।

ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ বাবে ডাঙৰ সকাহ

ক্ষুদ্ৰ আৰু অপ্ৰদূষণকাৰী উদ্যোগসমূহক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে নতুন বিধেয়ক অনা হ'ব। ইয়াৰ অধীনত তিনিবছৰলৈকে বিশেষ অনুমতি অবিহনে নিৰ্দিষ্ট ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ চলাব পৰা যাব। উদ্যোগ পামসমূহত উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ৰেহাই আগবঢ়োৱা হ'ব।

বিদেশ ভ্ৰমণৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ বাবে চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বিদেশ ভ্ৰমণত আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। অৱশ্যে যিকোনো বিদেশ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ আগতীয়া অনুমতি লোৱাটো বাধ্যতামূলক হ'ব।

অগৰ উদ্যোগৰ বাবে কেবিনেট কমিটি

অগৰ উদ্যোগৰ উন্নয়ন, ৰপ্তানি আৰু ব্যৱসায়িক সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্যে এখন বিশেষ কেবিনেট কমিটি গঠন কৰা হ'ব।

মাটি ক্ৰয়ৰ নিয়মত সংশোধন

বৰপেটা, মাজুলী, বটদ্ৰৱা আদি সত্ৰাঞ্চলত মাটি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যমান নিয়মসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সংশোধন কৰা হ'ব। বৰ্তমান বলবৎ থকা তিনিটা প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণ সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থাৰো পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব।

উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত

চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান পূৰ্বৰ দৰে অব্যাহত থাকিব আৰু চৰকাৰী ভূমি উদ্ধাৰৰ অভিযানত কোনো শিথিলতা অনা নহ'ব।

এই কেবিনেট সিদ্ধান্তসমূহে আইন-শৃংখলা, পৰ্যটন, উদ্যোগ, নগৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ স্পষ্ট কৰিছে। অৱশ্যে ঘোষণাসমূহৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰিব সময়মতে ৰূপায়ণ, স্বচ্ছতা আৰু জনসাধাৰণৰ বাস্তৱ উপকাৰ নিদ্ৰিশ্চত কৰাৰ ওপৰত।

গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত মোবাইল এৰি বাস্তৱ জীৱনক চিনি লওক : মুখ্যমন্ত্ৰী

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

গ্ৰীষ্মকালীন বিদ্যালয়ৰ বন্ধক কেৱল মোবাইল ফোন বা ডিজিটেল পৰ্দাত সীমাবদ্ধ নাৰাখি বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰে সমৃদ্ধ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ শিশু-কিশোৰসকলক আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ছচিয়েল মিডিয়াত শিশু-কিশোৰসকললৈ এখন মুকলি চিঠি প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে জীৱনৰ প্ৰকৃত শিক্ষা আৰু আনন্দ প্ৰকৃতি, পৰিয়াল আৰু সমাজৰ সৈতে জড়িত অভিজ্ঞতাৰ মাজতেই লুকাই থাকে।

চিঠিখনত তেওঁ নিজৰ শৈশৱৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি লিখিছে যে বিদ্যালয় বন্ধ মানেই আছিল নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণৰ সময়। মামাৰ ঘৰলৈ যোৱা, ককা-আইতাৰ লগত সময় কটোৱা, আত্মীয়-স্বজন আৰু বন্ধু-বান্ধৱৰ সৈতে খেল-ধেমালি কৰা, গছত উঠি ঋতুভিত্তিক ফল সংগ্ৰহ কৰা, পুখুৰীত মাছ ধৰা আৰু সন্ধিয়ালৈ পথাৰত ক্ৰিকেট বা ফুটবল খেলাৰ স্মৃতিয়ে আজিও তেওঁক আনন্দ দিয়ে।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, আধুনিক প্ৰযুক্তি, মোবাইল ফোন আৰু ইণ্টাৰনেটে জীৱন সহজ কৰি তুলিলেও বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ বিকল্প কেতিয়াও হব নোৱাৰে।

সেয়েহে বন্ধৰ দিনকেইটাত ককা-আইতা বা আত্মীয়ৰ সৈতে সময় কটোৱা, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ কাহিনী শুনা, বন্ধুবান্ধৱৰ সৈতে বাহিৰত খেল-ধেমালি কৰা, ভাল কিতাপ পঢ়া আৰু নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ শিশু-কিশোৰসকলক উৎসাহিত কৰে।

একেদৰে গ্ৰীষ্মকালীন ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰা পৰিয়ালসমূহক অসমৰ সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ সৈতে সন্তানক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁ অসম বিজ্ঞান নগৰ, শহীদ স্মাৰক আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম আদি ঐতিহাসিক আৰু শিক্ষামূলক স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়, যাতে নতুন প্ৰজন্মই নিজৰ ৰাজ্যৰ গৌৰৱময় ইতিহাস আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বিষয়ে অধিক জানিব পাৰে।

চিঠিখনত তেওঁ লুপ্তপ্ৰায় হৈ অহা চিঠি লিখাৰ অভ্যাস পুনৰ জীৱন্ত কৰি তোলাৰ বাবেও শিশু-কিশোৰসকলক আহ্বান জনায়। তেওঁৰ মতে, বন্ধু, শিক্ষক, আত্মীয় বা প্ৰিয় ব্যক্তিলৈ এখন হাতে লিখা চিঠিয়ে অনুভূতি অধিক গভীৰভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সৃজনশীলতা বিকাশত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে।

শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ অন্তত শিশু-কিশোৰসকল নতুন অভিজ্ঞতা, সৃষ্টিশীল চিন্তা আৰু আজীৱন মনত ৰৈ যোৱা সুন্দৰ স্মৃতিৰে বিদ্যালয়লৈ উভতি আহিব।

গুৱাহাটীত পৰিচ্ছন্নতা অভিযানত কঠোৰ জিএমচি

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

আৱৰ্জনা পেলোৱা, ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ-থুই দিয়া, নিষিদ্ধ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিলে তৎক্ষণাত স্পট ফাইন

গুৱাহাটী মহানগৰখনক অধিক পৰিষ্কাৰ, সুস্থ আৰু বাসোপযোগী নগৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটী মহানগৰ পালিকা নিগম -এ পৰিচ্ছন্নতা আইন বলৱৎ কৰাত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। জাৰি কৰা এক ৰাজহুৱা জাননীত নাগৰিকৰ দৈনন্দিন আচৰণৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও অপৰিচ্ছন্ন আৰু অসামাজিক কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগতে নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তৎক্ষণাত স্পট ফাইন আৰোপ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। জাননী অনুসৰি, ৰাজহুৱা স্থানত আৱৰ্জনা পেলোৱা, যতে-ততে ময়লা বা নিৰ্মাণ সামগ্ৰী নিক্ষেপ কৰা, ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ বা মলত্যাগ কৰা, থুই দিয়া, আৱৰ্জনা জ্বলাই দিয়া আৰু চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰা একবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। নিগমে স্পষ্ট কৰি দিছে যে মহানগৰখনত পৰিচ্ছন্নতা অভিযান অধিক ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ নিয়ম ভংগ কৰা ব্যক্তিৰ পৰা ঘটনাস্থলীতেই স্পট ফাইন সংগ্ৰহ কৰা হব। এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলৰ মাজত দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা স্থানসমূহ পৰিষ্কাৰ আৰু স্বাস্থ্যসম্মত কৰি ৰখাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। নিগমে সকলো নাগৰিকক নাগৰিক দায়িত্ব পালন কৰি পৰিচ্ছন্নতাৰ নিয়ম মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নিগমৰ মতে, এখন স্বচ্ছ, সুস্থ আৰু সেউজীয়া গুৱাহাটী গঢ়ি তোলাত প্ৰশাসনৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ সমানে প্ৰয়োজনীয়।

প্ৰৱাসী শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত বিধানসভা সৰগৰম

বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন, টোল-ফ্ৰী হেল্পলাইন আৰু নজৰদাৰী ব্যৱস্থা গঢ়াৰ দাবী; চৰকাৰৰ ইতিবাচক আশ্বাস

জন জন বিচাৰ
...গুৱাহাটী

বহিঃৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা অসমীয়া শ্ৰমিকসকলৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, শোষণ আৰু বিভিন্ন দুৰ্ভোগক লৈ বিধানসভাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে বিৰোধী দলে। শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন ব্যৱস্থা, বিশেষ হেল্পলাইন আৰু শক্তিশালী নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হয়।

বাজেট অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনৰ শূন্যকালত চেঙাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে বিষয়টো উত্থাপন কৰি কয় যে বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত অসমীয়া শ্ৰমিকৰ সঠিক তথ্য চৰকাৰৰ হাতত নথকাটো অতি চিন্তাজনক। ৰাজ্যৰ বহু যুৱক-যুৱতী জীৱিকাৰ সন্ধানত বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে যদিও তেওঁলোকৰ অৱস্থা, সুৰক্ষা আৰু অধিকাৰৰ বিষয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য নাই।

শ্ৰম কল্যাণ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে স্বীকাৰ কৰে যে বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত অসমীয়া শ্ৰমিকৰ সঠিক সংখ্যা চৰকাৰৰ হাতত উপলব্ধ নহয়। অৱশ্যে পঞ্জীয়ন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰে ইতিবাচকভাৱে বিবেচনা কৰিব বুলি তেওঁ সদনক আশ্বস্ত কৰে।

আলোচনাত উল্লেখ কৰা হয় যে ২০২৫ চনত আৰম্ভ হোৱা 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈ ৩৫৪ জন মৃত শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ অসমলৈ অনা হৈছে। কিন্তু কেৱল মৃত্যুৰ পিছত সহায় আগবঢ়োৱাতকৈ জীৱিত অৱস্থাতেই শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটোৱেই অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিৰোধীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে।

বিধায়কে বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱা প্ৰতিজন শ্ৰমিকৰ ব্যক্তিগত তথ্য, কৰ্মস্থলী, নিয়োগকৰ্তা আৰু ঠিকনা বাধ্যতামূলকভাৱে পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে ঠিকাদাৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহকো চৰকাৰৰ ওচৰত তথ্য দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ দাবী জনায়। লগতে জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত সহায় লাভৰ বাবে টোল-ফ্ৰী হেল্পলাইন আৰু আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হয়।

শেহতীয়াকৈ তামিলনাডুত গেছ নিৰ্গমনৰ ঘটনাত দুগৰাকী অসমীয়া মহিলা শ্ৰমিকৰ মৃত্যু আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা কেইবাজনো অসমীয়া যুৱকক উদ্ধাৰৰ ঘটনাই বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষাক লৈ নতুনকৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে।

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, পঞ্জীয়নভিত্তিক তথ্যভঁৰাল আৰু জৰুৰী সহায় ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠিলে শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে শোষণ, প্ৰতাৰণা আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰিব।

এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন মহানগৰ, যাতায়াত ব্যৱস্থা বিপৰ্যস্ত

মালিগাঁও, আমবাৰী, চান্দমাৰী, কাহিলীপাৰাকে ধৰি বহু অঞ্চলত জলাবদ্ধতা

জন জন বিচাৰ
...গুৱাহাটী

বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ একাধিক অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰে। কেইঘণ্টামান ধৰি হোৱা বৰষুণৰ পিছতে মালিগাঁও, আমবাৰী, ৰাজগড়, লেম্ব ৰোড, কাহিলীপাৰা, লখৰা ৰোড, বৰাগাঁও, শিলপুখুৰী আৰু চান্দমাৰীকে ধৰি মহানগৰীৰ বহু পথত পানী জমা হোৱাত যান-বাহন চলাচলত তীব্ৰ ব্যাঘাত ঘটে।

জোৰাবাট উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো পানীত ডুব যোৱাত তলৰ পথত যান চলাচল প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰে। ফলত দুয়োফালৰ বহু যানবাহন উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰেদি চলাচল কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাত তাতো দীঘলীয়া যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়।

মালিগাঁওকে ধৰি কেইবাটাও নিম্নাঞ্চলত আঁঠুলৈকে পানী উঠাৰ ফলত বহু ব্যক্তিগত বাহন, বাছ আৰু দু-চকীয়া বাহন পথতে বিকল হৈ পৰে। বিদ্যালয় বাছসমূহো জলাবদ্ধ পথত আবদ্ধ হৈ পৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়।

এফালে পুনৰ মহানগৰীত এজাক বৰষুণতে সৃষ্টি হোৱা জলাবদ্ধতাই নলা-নৰ্দমা ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলতা আৰু নগৰ পৰিকল্পনাৰ সীমাবদ্ধতাক উন্মোচিত কৰিছে। স্থানীয় বাসিন্দাসকলে জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ দাবী জনাইছে।

ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা মতে, অহা ১৪ জুলাইলৈ গুৱাহাটীত আকাশ ডাৱৰীয়া থকাৰ লগতে মাজে মাজে বৰষুণ আৰু বজ্ৰসহ বৃষ্টিপাত অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিম্নাঞ্চলসমূহত পুনৰ জলাবদ্ধতাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰি নাগৰিকসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি যাতায়াতৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে।

দুমাহৰ বাবে যান-বাহন চলাচল বন্ধ থাকিব পুৰণি শৰাইঘাট সেতু

জন জন বিচাৰ
...গুৱাহাটী

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক পুৰণি শৰাইঘাট সেতুত বৃহৎ পৰিসৰৰ মেৰামতি আৰু শক্তিবৃদ্ধিৰ কামৰ বাবে অহা ১৩ জুলাইৰ পৰা ১৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ সেতুখন সকলো ধৰণৰ যান-বাহন চলাচলৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। এই কথা ৭ জুলাইত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে কামৰূপ মেট্ৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত স্বপ্নীল পলে।

ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই সেতুখনৰ বহুদিনীয়া গাঁথনিৰ জৰুৰী মেৰামতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক অৱগত কৰাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত কামৰূপ মেট্ৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী, পৰিবহণ বিভাগ আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ মাজত কেইবাখনো সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহত মেৰামতিৰ সময়ছোৱাত যান-বাহন চলাচল স্বাভাৱিকভাৱে চলাই নিয়াৰ বাবে বিস্তৃত বিকল্প যান-ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হয়।

উপায়ুক্ত স্বপ্নীল পলে কয় যে সকলো অংশীদাৰ সংস্থাৰ সৈতে আলোচনা-মৰ্মে এই দুমহীয়া বন্ধৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰা হৈছে, যাতে মেৰামতিৰ কাম কোনো বাধা নোহোৱাকৈ সম্পন্ন কৰিব পৰা যায়।

বন্ধৰ সময়ছোৱাত কামৰূপ মেট্ৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ মাজত চলাচল কৰা সকলো যানবাহন নতুন শৰাইঘাট সেতুৰে চলাচল কৰিব। একে সময়তে, যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণ, যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন যান-বাহন চলাচল অব্যাহত ৰাখিবলৈ বিশেষ ট্ৰেফিক ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হ'ব। জিলা প্ৰশাসনে সাধাৰণ ৰাইজক ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ, নিৰ্ধাৰিত বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু সম্ভাৱ্য অসুবিধা এৰাবলৈ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে উপযুক্ত পৰিকল্পনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।

পুৰণি শৰাইঘাট সেতু অসমৰ এক ঐতিহাসিক তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগস্থল। সেতুখনৰ এই জৰুৰী মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ সুৰক্ষা আৰু স্থায়িত্ব অধিক শক্তিশালী হ'ব বুলি প্ৰশাসনে আশা প্ৰকাশ কৰিছে।

এই সপ্তাহৰ ৰাশিফল

১০-০৭-২০২৬১ পৰা ১৬-০৭-২০২৬লৈ

মেষ ঃ ঘৰুৱা সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাব। অদৰকাৰী বাদ-বিবাদৰ পৰা বিৰত থাকক। কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম লাভ কৰিব।

বৃষ ঃ শৰীৰৰ স্বাস্থ্যযৰ প্ৰতি যত্ন লওক। মানসিক উদ্বিগ্নতাৰ প্ৰতি সচেতন হওক। চেষ্টাত সফলতা লাভ কৰিব।

মিথুন ঃ অদৰকাৰী কামত সময় অপচয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। আৰ্থিক দিশ শুভ। শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যত্ন লওক।

কৰ্কট ঃ কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব। অদৰকাৰী খৰচৰ পৰা সাৱধান হওক। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সময় শুভ।

সিংহ ঃ কৰ্মক্ষেত্ৰত অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব পাৰে। ভ্ৰমণৰ পৰা মানসিক আনন্দ লাভ কৰিব। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সময় শুভ।

কন্যা ঃ কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব পাৰে। পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লওক। আকস্মিক ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে।

তুলা ঃ কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব। শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সময় শুভ।

বৃশ্চিক ঃ অদৰকাৰী বাদ-বিবাদৰ পৰা বিৰত থাকক। আৰ্থিক দিশ শুভ। ভাগ্যৰ সহায় লাভ কৰিব।

ধনু ঃ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মতানৈক্য আহিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব। অদৰকাৰী বাদ-বিবাদৰ পৰা বিৰত থাকক।

মকৰ ঃ চেষ্টাত সফলতা লাভ কৰিব। মানসিক সুখ-শান্তি বজাই থাকিব। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সময় শুভ।

কুম্ভ ঃ মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব পাৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সাৱধানে গ্ৰহণ কৰক। কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে প্ৰশংসা লাভ কৰিব।

মীন ঃ মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব পাৰে। অত্যাধিক আনন্দ-ফূৰ্তিয়ে অপযশ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। আৰ্থিক দিশ শুভ থাকিব।

-হিতেন শৰ্মা শাস্ত্ৰী
অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠ, অসম শাখা
যোগাযোগ : ৯৮৫৪০২৬৭৭৯

অসমত ব্যৱসা আৰম্ভ কৰা হ'ল অধিক সহজ

ক্ষুদ্ৰ, দূষণমুক্ত উদ্যোগক প্ৰথম তিনি বছৰৰ বাবে চৰকাৰী অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন নহব

জন জন বিচাৰ ...গুৱাহাটী

অসমত উদ্যোগ স্থাপন অধিক সহজ কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি ঘোষণা কৰিছে। নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু দূষণমুক্ত উদ্যোগসমূহে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰথম তিনি বছৰৰ বাবে কোনো চৰকাৰী অনুমোদন বা লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব। এই সিদ্ধান্তই বিশেষকৈ ষ্টাৰ্টআপ, মাইক্ৰ', ক্ষুদ্ৰ আৰু মধ্যম উদ্যোগ তথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদ্যোগ আৰম্ভ কৰা যুৱ উদ্যোক্তাসকলক যথেষ্ট সকাহ দিব বুলি আশা কৰা হৈছে।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে উদ্যোগপতিসকলে মূল্য সৃষ্টি, নতুন কৰ্মসংস্থান আৰু ব্যৱসায়ৰ বিকাশত মনোনিবেশ কৰিব লাগে, চৰকাৰী অনুমোদনৰ বাবে দৌৰি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। এই পদক্ষেপৰ মূল লক্ষ্য হৈছে 'ইজ আফ ডুইংগ বিজনেস' অধিক শক্তিশালী কৰি অসমক বিনিয়োগৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলা।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, যিসমূহ উদ্যোগে পৰিৱেশৰ ওপৰত নগণ্য বা কোনো নেতিবাচক প্ৰভাৱ নপেলায়, সেই উদ্যোগসমূহ এই নীতিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। চৰকাৰে শীঘ্ৰেই কোনবোৰ উদ্যোগ এই

সুবিধাৰ আওতাত আহিব আৰু তিনি বছৰৰ পিছত কেনেধৰণৰ নিয়ম পালন কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে বিশদ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব।

শেহতীয়া বছৰসমূহত অসম চৰকাৰে অনলাইন সেৱা, একক-জাননী ব্যৱস্থা, বিনিয়োগ সন্মিলন আৰু উদ্যোগবান্ধৱ নীতি গ্ৰহণৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনক উদ্যোগৰ নতুন গন্তব্যস্থল হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। নতুন সিদ্ধান্তই উদ্যোগ স্থাপনৰ সময় আৰু ব্যয় দুয়োটা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ, উদ্ভাৱন আৰু স্থানীয় উদ্যোগীকৰণক অধিক গতি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।

ব্যৱসায়ী মহলে এই ঘোষণাক আদৰণি জনাই কয় যে, অনুমোদন লাভৰ দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া নতুন উদ্যোগৰ অন্যতম ডাঙৰ বাধা আছিল। চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে সেই বাধা বহুখিনি দূৰ কৰি ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক বিকাশ আৰু কৰ্মসংস্থান সৃষ্টিত নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব।

নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলনীৰ নতুন সমিতি গঠন

জন জন বিচাৰ ...নাজিৰা

ঐতিহ্যমণ্ডিত নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলনীৰ এখন সাধাৰণ সভা বিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈ নতুন কাৰ্যকৰী সমিতি গঠন কৰা হয়। ১৯০২ চনত প্ৰতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সম্পৰ্ক

অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক আৰু সামগ্ৰিক উন্নয়নত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণৰ লক্ষ্যৰে সভাখন অনুষ্ঠিত হয়। সন্মিলনীৰ সভাপতি অজিত খাটনিয়াৰ সভাপতিত্বত আৰু সম্পাদক দিলীপ ফুকনৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত সভাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অৰ্ধশতাধিক প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বিদ্যালয় জীৱনৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰাৰ লগতে মাতৃ প্ৰতিষ্ঠানৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। সভাত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অজয় কুমাৰ গগৈয়েও প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।

সভাত গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসৰি প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তক সভাপতি, মৃদুল মহন্তক কাৰ্যকৰী সভাপতি, ধীৰেণ ফুকন আৰু চৈয়দ মহচীন হুছেইনক সম্পাদক, গুণ গোবিন্দ দত্তক কোষাধ্যক্ষ হিচাপে লৈ নতুন কাৰ্যকৰী সমিতি গঠন কৰা হয়। দেৱ বৰুৱা, ডঃ অজয়লাল বৰুৱা, যদু দত্ত, অজিত খাটনিয়াৰ আৰু দিলীপ ফুকনক উপদেষ্টা হিচাপে মনোনীত কৰা হয়। লগতে নৃপেন গগৈ, আব্দুৰ ৰহমান, গোপাল বৰুৱা আৰু ময়ুৰ কুমাৰ গগৈক উপ-সভাপতি কৰা হয়।

অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন

জন জন বিচাৰ ...নাজিৰা

অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ ৪৫ সংখ্যক দ্বি-বাৰ্ষিক ৰাজ্যিক অধিৱেশন অহা ২২, ২৩ আৰু ২৪ জুলাইত নাজিৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব। নাজিৰা মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আতিথ্যত গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা এই তিনিদিনীয়া অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ গতিত চলি থকাৰ কথা সংবাদমেলযোগে জানিবলৈ দিয়ে আদৰণী সমিতিয়ে।

২২, ২৩ আৰু ২৪ জুলাইত নাজিৰাত

আদৰণী সমিতিৰ সভাপতি ডঃ সব্যসাচী মহন্ত আৰু সম্পাদক শৈলেন্দ্ৰ কলিতাই জনোৱা মতে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষক প্ৰতিনিধিসকল অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। পতাকা উত্তোলন, প্ৰতিনিধি সভা, বিষয়-বাছনি সভা, আলোচনা চক্ৰ, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে 'অমৃত কণ্ঠ' জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত পঢ়িবলৈ শিকোঁ আহক শীৰ্ষক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আৰু শিশু শ্ৰম বিৰোধী সজাগতা পোষ্টাৰ উন্মোচনো অনুষ্ঠিত হ'ব।

অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগু, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্ৰী বিমল বৰা, মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাইকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। অধিৱেশন সফল কৰি তুলিবলৈ আদৰণী সমিতিয়ে শিক্ষক, অভিভাৱক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে।

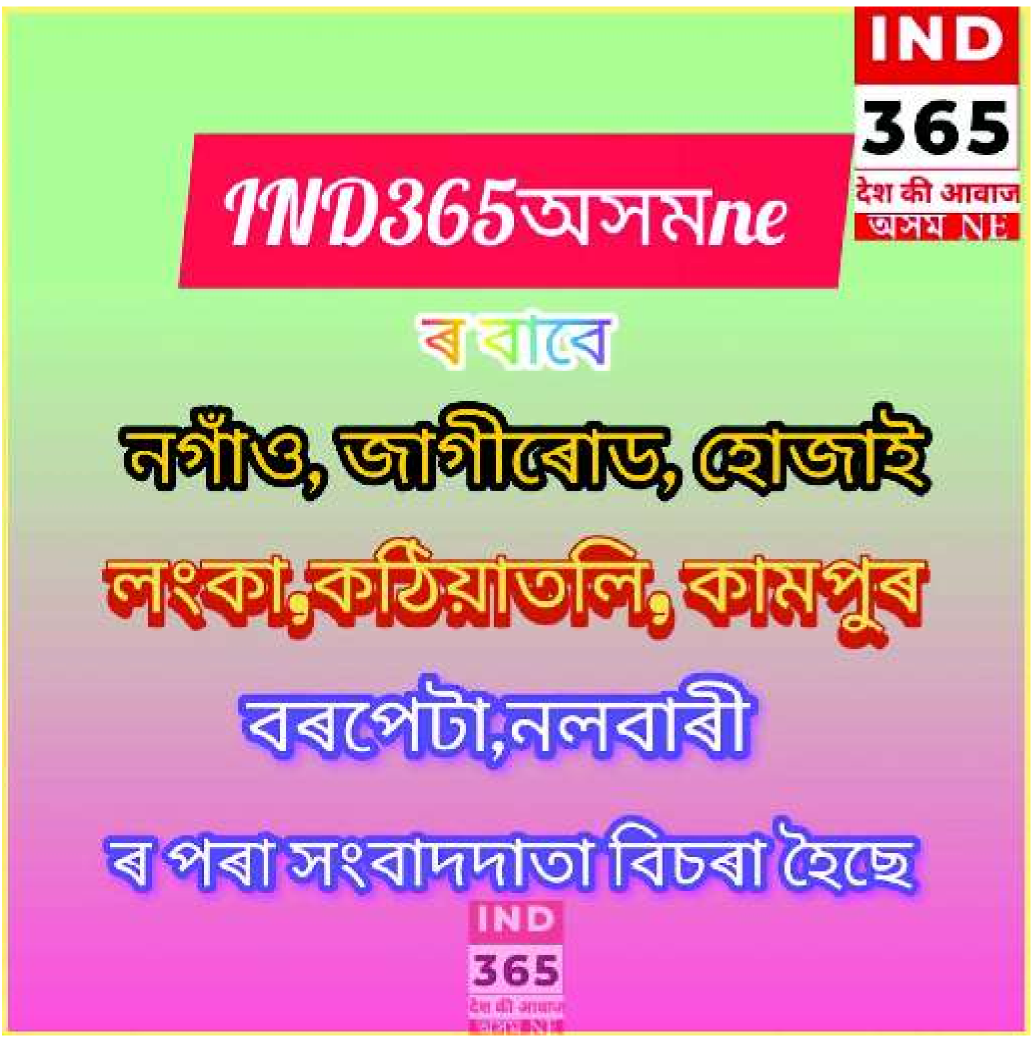

সম্পাদকীয়

আস্থাৰ মুখোছত সুযোগবাদী ৰাজনীতি

অযোধ্যাৰ শ্ৰীৰাম জন্মভূমি মন্দিৰৰ চঢ়োৱা আত্মসাৎ সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগে দেশজুৰি গভীৰ উদ্বেগ আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে। কোটি কোটি ভক্তৰ বিশ্বাসত গঢ়ি উঠা এই পৱিত্ৰ স্থানত যদি কোনো ধৰণৰ অনিয়ম সংঘটিত হয়, তেন্তে সেয়া কেৱল আৰ্থিক অপৰাধ নহয়, জনআস্থাৰ ওপৰত আঘাত বুলিও গণ্য হয়। সেয়েহে এই ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ, স্বচ্ছ আৰু দ্ৰুত তদন্ত সময়ৰ দাবী।

কিন্তু এই সংবেদনশীল বিষয়ক লৈ যিদৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ-প্ৰত্যাৰোপ আৰম্ভ কৰিছে, সেয়া দুখজনক। আস্থা, ধৰ্ম আৰু মন্দিৰৰ দৰে বিষয় ৰাজনৈতিক লাভ-লোকচনৰ হাতিয়াৰ হব নালাগে। শাসক হওক বা বিৰোধী-সকলো পক্ষৰ প্ৰথম দায়িত্ব হল সত্য উদঘাটন আৰু দোষীক আইন অনুসৰি শাস্তি নিশ্চিত কৰা।

গণতন্ত্ৰত বিৰোধী পক্ষৰ চৰকাৰক জবাবদিহি কৰোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু সমালোচনা যদি কেৱল ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভৰ উদ্দেশ্যে হয়, তেন্তে তাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষীণ হয়। একেদৰে, শাসক পক্ষইও এই ঘটনাক সামান্য বুলি উলাই নেদেখি, তদন্ত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে আগবঢ়াই জনসাধাৰণৰ আস্থা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব।

মন্দিৰ কেৱল পূজাৰ স্থান নহয়; ই সমাজৰ নৈতিকতা, বিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰো প্ৰতীক। সেইবাবে মন্দিৰৰ ধন-সম্পত্তিৰ ব্যৱস্থাপনাত অধিক স্বচ্ছতা, আধুনিক নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু কঠোৰ জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়।

ধৰ্মীয় আস্থাক ৰাজনৈতিক মঞ্চত প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয় নকৰি, ইয়াক সুৰক্ষিত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো পক্ষই সংযম, দায়িত্ববোধ আৰু পৰিপক্কতা প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত। শেষত, জনতাৰ বিশ্বাসেই যিকোনো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি। সেই বিশ্বাস অটুট ৰখাটো সকলোৰে সামূহিক দায়িত্ব।

২৯ কোটি মুছলমানৰ দেশত শিৱধাম

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

বিশ্বৰ সৰ্বাধিক মুছলমান জনসংখ্যাৰ দেশ ইণ্ডোনেছিয়া। প্ৰায় ২৯ কোটি মুছলমানৰ এই দেশখনত আজিও গৌৰৱেৰে থিয় হৈ আছে এক বিশাল শিৱ মন্দিৰ-প্ৰাম্বানান (Prambanan)। ই কেৱল ইণ্ডোনেছিয়াৰেই নহয়, সমগ্ৰ দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য হিন্দু মন্দিৰ কমপ্লেক্স। প্ৰায় ১,১৭০ বছৰৰ ইতিহাস বহন কৰা এই স্থাপত্য আজিও ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজৰ প্ৰাচীন সভ্যতাগত আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ এক জীৱন্ত নিদৰ্শন।

সম্প্ৰতি ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই এই বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলীৰ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে এক যৌথ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ পিছত পুনৰ বিশ্বজুৰি আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে প্ৰাম্বানান।

৯ম শতিকাৰ এক অনন্য স্থাপত্য

জাভা দ্বীপৰ যোগ্যকাৰ্টাৰ ওচৰত অৱস্থিত প্ৰাম্বানান মন্দিৰ কমপ্লেক্সৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল খ্ৰীষ্টীয় ৯ম শতিকাৰ মাজভাগত, প্ৰায় ৮৫০ খ্ৰীষ্টাব্দত। ইতিহাসবিদসকলৰ মতে, হিন্দু মাতাৰাম সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা ৰাকাই পিকাটান-এ এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে ইয়াক সম্পূৰ্ণ ৰূপ দিয়ে।

এই মন্দিৰ কমপ্লেক্স মূলতঃ প্ৰায় ২৪০টা মন্দিৰেৰে গঠিত আছিল। ইয়াৰ কেন্দ্ৰস্থলত আছে হিন্দু ত্ৰিমূৰ্তিক উৎসৰ্গিত তিনিটা মুখ্য মন্দিৰ-ভগৱান শিৱ, বিষ্ণু আৰু ব্ৰহ্মা। ইয়াৰে প্ৰায় ৪৭ মিটাৰ উচ্চতাৰ শিৱ মন্দিৰটো সমগ্ৰ কমপ্লেক্সৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য।

পাথৰত খোদিত ৰামায়ণ

প্ৰাম্বানানৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈছে ইয়াৰ অনুপম ভাস্কৰ্যশিল্প। মন্দিৰৰ দেৱাল আৰু গেলাৰীত ৰামায়ণ আৰু কৃষ্ণকেন্দ্ৰিক হিন্দু আখ্যানসমূহ সূক্ষ্ম নক্সা আৰু ভাস্কৰ্যৰ জৰিয়তে খোদিত কৰা হৈছে। এই শিল্পকলা প্ৰমাণ কৰে যে ভাৰতীয় সাহিত্য, ধৰ্ম আৰু স্থাপত্যশৈলীয়ে শতাব্দীৰ আগতেই দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সমাজ-সংস্কৃতিক গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিল।

আজিও প্ৰাম্বানান মন্দিৰ চৌহদত নিয়মীয়াকৈ 'ৰামায়ণ বেলেট' মঞ্চস্থ হয়। স্থানীয় শিল্পীসকলৰ অভিনয়ত উপস্থাপিত এই নৃত্য-নাট্য বিশ্বজুৰি পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ।

জাভা দ্বীপৰ যোগ্যকাৰ্টাৰ ওচৰত অৱস্থিত প্ৰাম্বানান মন্দিৰ কমপ্লেক্সৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল খ্ৰীষ্টীয় ৯ম শতিকাৰ মাজভাগত, প্ৰায় ৮৫০ খ্ৰীষ্টাব্দত। ইতিহাসবিদসকলৰ মতে, হিন্দু মাতাৰাম সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা ৰাকাই পিকাটান-এ এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে ইয়াক সম্পূৰ্ণ ৰূপ দিয়ে।

এই মন্দিৰ কমপ্লেক্স মূলতঃ প্ৰায় ২৪০টা মন্দিৰেৰে গঠিত আছিল। ইয়াৰ কেন্দ্ৰস্থলত আছে হিন্দু ত্ৰিমূৰ্তিক উৎসৰ্গিত তিনিটা মুখ্য মন্দিৰ-ভগৱান শিৱ, বিষ্ণু আৰু ব্ৰহ্মা। ইয়াৰে প্ৰায় ৪৭ মিটাৰ উচ্চতাৰ শিৱ মন্দিৰটো সমগ্ৰ কমপ্লেক্সৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য।

ধ্বংসস্তূপৰ পৰা বিশ্ব ঐতিহ্যলৈ

১০ম শতিকাৰ পিছত ৰাজনৈতিক কেন্দ্ৰ সলনি হোৱা আৰু মাউণ্ট মেৰাপি আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণৰ ফলত এই মন্দিৰ ধীৰে ধীৰে পৰিত্যক্ত হৈ পৰে। ইয়াৰ পিছত কেইবাটাও শক্তিশালী ভূমিকম্পই বহু মন্দিৰ ধ্বংস কৰে।

১৯শ শতিকাত ডাচ প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে ইয়াৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰে। স্বাধীনতাৰ পিছত ইণ্ডোনেছিয়াই ব্যাপক সংৰক্ষণ অভিযান চলায়। এই ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক মূল্যৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে ১৯৯১ চনত ইউনেস্কোৱে প্ৰাম্বানানক বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে।

সংৰক্ষণত ভাৰতৰ সহযোগিতা

ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজত হোৱা সাম্প্ৰতিক সহযোগিতা চুক্তিৰ অধীনত ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপ-এ প্ৰাম্বানান মন্দিৰৰ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰত কাৰিকৰী সহযোগিতা আগবঢ়াব। এই কামত মূল শিলসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি ঐতিহাসিক গাঁথনি সংৰক্ষণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃত **এনাষ্টাইলক্সছিছ** পদ্ধতি অনুসৰণ কৰা হব।

এই প্ৰকল্পক কেৱল সংৰক্ষণ অভিযান বুলি নহয়, ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজৰ প্ৰাচীন সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলিও গণ্য কৰা হৈছে।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণ

ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোগ্যকাৰ্টা ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰাম্বানান মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰি সংৰক্ষণ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে। তেওঁ এই মন্দিৰক ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজৰ বহু শতিকাজুৰি চলি অহা সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ এক জীৱন্ত প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰে।

ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ চিহ্ন আজিও স্পষ্ট

ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাতীয় জীৱনত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বহু নিদৰ্শন আজিও লক্ষ্য কৰিব পাৰি। দেশখনৰ জাতীয় বিমান সংস্থাৰ নাম গৰুড়া ইণ্ডোনেছিয়া, যাৰ নাম হিন্দু পৌৰাণিক গৰুড়ৰ পৰা আহিছে। জাভা আৰু বালিত আজিও ৰামায়ণ-মহাভাৰতৰ কাহিনী নৃত্য, নাটক আৰু শিল্পকলাৰ মাজেৰে জীয়াই ৰখা হৈছে। বিশেষকৈ বালি দ্বীপত হিন্দু ধৰ্ম আজিও সামাজিক জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ।

সভ্যতাৰ এক অবিনাশী সেতু

প্ৰাম্বানান মন্দিৰ কেৱল এটা পূজাস্থলী নহয়। ই ভাৰত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শতাব্দীৰ পৰ শতাব্দী ধৰি চলি অহা সামুদ্ৰিক বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু জ্ঞানচৰ্চাৰ এক জীৱন্ত দলিল। ইয়াৰ প্ৰতিটো শিল, প্ৰতিটো ভাস্কৰ্য আৰু প্ৰতিটো অলংকৰণে ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজত গঢ়ি উঠা ঐতিহাসিক সম্পৰ্কৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰে।

ধৰ্ম, ভাষা বা ৰাজনীতিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেনেদৰে যুগে যুগে মানুহক এক সূত্ৰত বান্ধি ৰাখিব পাৰে, প্ৰাম্বানান মন্দিৰ তাৰেই এক উজ্জ্বল উদাহৰণ। আজিৰ যুগত ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ যৌথ সংৰক্ষণ উদ্যোগে এই অমূল্য ঐতিহ্যক ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ বন্ধুত্ব আৰু সভ্যতাগত সম্পৰ্কক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে।

বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অভিযান তীব্ৰ

তামিলনাডুত ৫০ জন আটক, পশ্চিমবংগতো গ্ৰেপ্তাৰ; সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু নিৰ্বাসন প্ৰক্ৰিয়াত জোৰ

জন জন বিচাৰ
...✍নতুন দিল্লী

দেশজুৰি অবৈধভাৱে বসবাস কৰা বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অধিক তীব্ৰ কৰি তুলিছে কেন্দ্ৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আইন-শৃংখলা বাহিনীয়ে। শেহতীয়া ঘটনাক্ৰমত তামিলনাডুত আটক কৰা পুঞ্জ জন বাংলাদেশী নাগৰিকক নিৰ্বাসন প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে পদ্ৰিশ্চমবংগলৈ পঠিওৱা হৈছে। আনহাতে, পদ্ৰিশ্চমবংগৰ মুৰ্শিদাবাদ জিলাতো জ্ঞ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।

তামিলনাডুৰ পৰা সীমান্তলৈ

তামিলনাডু আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, আটক কৰা ৫০ জনৰ ভিতৰত ৪৪ জন পুৰুষ আৰু ৬ জন মহিলা আছে। তেওঁলোকক চেলম জিলাৰ বিশেষ নিৰুদ্ধ শিবিৰত ৰখা হৈছিল। চৰকাৰী নিৰ্দেশ লাভ কৰাৰ পিছত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে তেওঁলোকক তিৰুচিৰাপল্লীলৈ নিয়া হয় আৰু তাৰ পৰা ৰেলযোগে পশ্চিমবংগলৈ পঠিওৱা হয়।

পশ্চিমবংগৰ হৰিদাসপুৰ স্থল সীমান্তত তেওঁলোকক সীমা সুৰক্ষা বাহিনী (বিএছএফ)-ৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ পিছত বাংলাদেশ কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত হস্তান্তৰৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ কথা জানোৱা হৈছে।

মুৰ্শিদাবাদতো অভিযান

পশ্চিমবংগৰ মুৰ্শিদাবাদ জিলাৰ ভগৱানগোলা ৰেল ষ্টেচন চৌহদত সন্দেহজনকভাৱে ঘূৰি ফুৰা ৯ জন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত তেওঁলোক বাংলাদেশী নাগৰিক বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে।

অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাসমূহে এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে- তেওঁলোকে কেনেকৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল, কোনে আশ্ৰয় দিছিল, কত কাম কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো মানৱ সৰবৰাহ বা জাল নথিপত্ৰ চক্ৰ জড়িত আছে নেকি।

দেশজুৰি কঠোৰ অভিযান

কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সমন্বয়ত সীমা সুৰক্ষা বাহিনী, আৰক্ষী আৰু বিদেশী পঞ্জীয়ন কৰ্তৃপক্ষই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিনাক্তকৰণ আৰু নিৰ্বাসন প্ৰক্ৰিয়া তীব্ৰতৰ কৰিছে।

দিল্লীতো শেহতীয়াকৈ ৬৬ জন বিদেশী নাগৰিকক ভিছা নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে বুলি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে।

সীমান্ত সুৰক্ষা অধিক জোৰদাৰ

সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ কেৱল সীমান্তৰ সমস্যা নহয়; ই জাতীয় সুৰক্ষা, নথিপত্ৰ জালিয়াতি, মানৱ সৰবৰাহ, অবৈধ নিয়োগ আৰু আইন-শৃংখলাৰ সৈতে জড়িত এক বহুমুখী প্ৰত্যাহ্বান।

সেয়ে সীমান্তত কটকটীয়া নিৰীক্ষণ, উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু আন্তঃৰাজ্য সমন্বয় অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে।

অস্তিত্বহীন হাস্পতালত ৬ বছৰ ধৰি নিযুক্তি-বদলি

ইন্দোৰ। এখন হাস্পতাল নাই, নাই কোনো ভৱন, নাই এটুকুৰা মাটিও। কিন্তু চৰকাৰী নথি-পত্ৰত সেই হাস্পতাল পূৰ্ণাংগভাৱে চলি আছে। কেৱল সেয়াই নহয়, বিগত ছয় বছৰ ধৰি সেই অস্তিত্বহীন হাস্পতালৰ নামত চিকিৎসক, নাৰ্ছ, ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু লেব টেকনিচিয়ানসহ ৮৭ গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ নিযুক্তি, বদলি আৰু দৰমহা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াও অব্যাহত আছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশত চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে।

২৩ জুন, ২০২০ত মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে ইন্দোৰৰ খাজৰানা অঞ্চলত ১০০খন বিচনাযুক্ত এখন অসামৰিক হাস্পতাল স্থাপনৰ অনুমোদন দিছিল। এই প্ৰকল্পৰ বাবে চৰকাৰে কেইবাকোটি টকা অনুমোদন কৰাৰ লগতে ৮৭ চৰকাৰী পদো মঞ্জুৰ কৰিছিল।

কিন্তু অনুমোদনৰ ছয় বছৰ পাৰ হ'লেও হাস্পতাল নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ নহ'ল। কাৰণ হিচাপে দেখুওৱা হৈছে- উপযুক্ত মাটিৰ অভাৱ।

অভিযোগ অনুসৰি, হাস্পতালখন বাস্তৱত অস্তিত্বহীন হ'লেও চৰকাৰী নথিত ইয়াৰ নামতে চিকিৎসক, ষ্টাফ নাৰ্ছ, ফাৰ্মাচিষ্ট, লেব টেকনিচিয়ান আদি কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তি আৰু বদলিৰ আদেশ জাৰি হৈ আহিছে।

সম্প্ৰতি এজন লেব টেকনিচিয়ানৰ বদলিৰ নিৰ্দেশ জাৰি হোৱাৰ পিছতেই বিষয়টো পোহৰলৈ আহে আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সূচনা হয়।

বিতৰ্ক বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত স্বাস্থ্য বিভাগে স্পষ্টীকৰণ দি কয় যে খাজৰানা হাস্পতালৰ বাবে অনুমোদিত কৰ্মচাৰীসকলক ইন্দোৰৰ বিভিন্ন চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ-যেনে পি. চি. শেঠী হাস্পতাল, হুকুমচান্দ হাস্পতাল আৰু সঞ্জীৱনী ক্লিনিক-ত কৰ্মৰত কৰা হৈছিল।

কিন্তু চৰকাৰী নথি-পত্ৰত তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থল হিচাপে এতিয়াও খাজৰানা অসামৰিক হাস্পতাল বুলিয়েই উল্লেখ থকাত প্ৰশাসনৰ ওপৰত অধিক প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে।

বিৰোধী কংগ্ৰেছে ঘটনাক বৃহৎ চৰকাৰী কেলেংকাৰীক্ট বুলি অভিহিত কৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে।

আমেৰিকাত ৮৫ হাজাৰ, ভাৰতত মাত্ৰ ৩৫ টকা

ঔষধৰ মূল্যত ইমান বিশাল পাৰ্থক্য কিয় ?

জন জন বিচাৰ
...✍নতুন দিল্লী

যি ঔষধ আমেৰিকাত কিনিবলৈ প্ৰায় ৮৫ হাজাৰ টকা খৰচ হয়, সেই একেধৰণৰ ঔষধ ভাৰতত ৩৫ টকাৰ পৰা কেইশ টকাৰ ভিতৰতে পোৱা যায়। শেহতীয়াকৈ এগৰাকী আমেৰিকান মহিলাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এই মন্তব্যই সমগ্ৰ বিশ্বত আলোচনাৰ সৃষ্টি কৰিছে।

এই ঘটনাই কেৱল ভাৰতৰ ঔষধ উদ্যোগৰ শক্তিকেই নহয়, বিশ্বজুৰি চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু ঔষধৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ বৈষম্যকো পুনৰ উন্মোচন কৰিছে।

কি কৈছে আমেৰিকান মহিলাগৰাকীয়ে ?

সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত এটা দৃশ্যত মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ পেহীয়েক ৰক্ত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত। চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধটোৰ বাবে আমেৰিকাত প্ৰায় ৯০০ আমেৰিকান ডলাৰ প্ৰায় ৮৫ হাজাৰ ব্যয় কৰিবলগীয়া হয়। অথচ ভাৰতত একেই ঔষধৰ জেনেৰিক বিকল্প ৩৫ৰে পৰা ৩০০ টকাৰ ভিতৰত পোৱা যায়।

তেওঁৰ ভাষাত, আমেৰিকাত ঔষধৰ মূল্যই ৰোগীক লুটি লৈছে।

কিয় ইমান পাৰ্থক্য ?

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ইয়াৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে-

ভাৰত বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ সমমূল্যৰ ঔষধ 'জেনেৰিক ঔষধ' উৎপাদক।

বহু ঔষধৰ স্বত্বাধিকাৰৰ মেয়াদ শেষ হোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কম মূল্যত সেই ঔষধ উৎপাদন কৰিব পাৰে।

দেশত বহু অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ মূল্য ঔষধ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়।

বৃহৎ পৰিসৰত উৎপাদন হোৱাৰ বাবে উৎপাদন ব্যয়ো কম হয়।

সমমূল্যৰ ঔষধ কি ?

সমমূল্যৰ ঔষধ হৈছে এনে ঔষধ যাৰ ঔষধীয় গুণ, কাৰ্যক্ষমতা, গুণগত মান আৰু সুৰক্ষা মূল নামী ঔষধৰ সমান, কিন্তু মূল্য যথেষ্ট কম।

চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে এনে ঔষধে লাখ লাখ ৰোগীৰ চিকিৎসা ব্যয় হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে।

বিশ্বৰ ঔষধ ভঁৰাল ভাৰত

ভাৰতক আজিৰ দিনত বিশ্বজুৰি 'বিশ্বৰ ঔষধ ভঁৰাল' বুলি কোৱা হয়।

বিশ্বৰ ২০০ৰো অধিক দেশলৈ ভাৰতৰ পৰা ঔষধ ৰপ্তানি হয়।

যক্ষ্মা, এইডছ, কৰ্কট ৰোগ, বহুমূত্ৰ ৰোগ আদি বহু জটিল ৰোগৰ সুলভ ঔষধ ভাৰত উৎপাদন কৰে।

কভিড মহামাৰীৰ সময়তো ভাৰত বহু দেশলৈ জীৱন ৰক্ষাকাৰী ঔষধ আৰু প্ৰতিষেধক যোগান ধৰিছিল।

তথাপিও ভাৰতত চিকিৎসা সকলোৰে বাবে সুলভ নেকি ?

উন্নত দেশৰ তুলনাত ভাৰতত ঔষধৰ মূল্য কম হলেও বহু ভাৰতীয় পৰিয়ালৰ বাবে চিকিৎসা ব্যয় আজিও এক ডাঙৰ সমস্যা।

বিশেষকৈ- কৰ্কট ৰোগ, হৃদৰোগ, বৃক্ক বিকলতা, অংগ সংস্থাপন, নিবিড় চিকিৎসা

এই ক্ষেত্ৰসমূহত বহু পৰিয়ালে নিজৰ সঞ্চয় শেষ কৰিবলগীয়া হয়।

সচেতনতা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঔষধ

বিশেষজ্ঞসকলে স্পষ্টকৈ কয়-কেৱল কম মূল্য দেখি ঔষধ ক্ৰয় কৰা উচিত নহয়। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি উপযুক্ত ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰাটোৱেই সুৰক্ষিত পথ।

সচেতন ৰোগী, সুলভ চিকিৎসা আৰু শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থাই এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰে।

ঔষধৰ মূল্যৰ এই বিশাল পাৰ্থক্যই ভাৰতৰ ঔষধ উদ্যোগৰ সক্ষমতাক প্ৰতিফলিত কৰে। অৱশ্যে কোনো ঔষধৰ মূল্য তুলনা কৰাৰ সময়ত ব্ৰেণ্ডযুক্ত ঔষধ, সমমূল্যৰ ঔষধ, ঔষধৰ মাত্ৰা, স্বত্বাধিকাৰৰ অৱস্থা আৰু সংশ্লিষ্ট দেশৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ ব্যৱস্থা বিবেচনা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সঠিক তথ্য, বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা আৰু সুলভ স্বাস্থ্যসেৱাইহে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ মূল আধাৰ।

সতলজ: নিষিদ্ধ চলচ্চিত্ৰ নে ইতিহাসৰ অশুনা কাহিনী

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

মানৱাধিকাৰ কৰ্মী জস্বন্ত সিং খালড়াৰ জীৱন আৰু সংগ্ৰামৰ ওপৰত নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰ ‘সতলজ’ পুনৰ দেশজুৰি আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। অটিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তিৰ মাত্ৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ছবিখন আঁতৰাই দিয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াক লৈ ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক মহলত তীব্ৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে।

এই পৰিস্থিতিত দিল্লী শিখ গুৰুদ্বাৰা প্ৰবন্ধক সমিতি এ ছবিখনৰ সমৰ্থনত আগবাঢ়ি আহি ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত ছবিখনৰ জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিব। সমিতিৰ সভাপতি হৰমীত সিং কালকাই কয়, ছবিখনত পঞ্জাবত সংঘটিত বুলি অভিযোগ থকা মানৱাধিকাৰ উলংঘন আৰু জস্বন্ত সিং খালড়াৰ সত্য উদঘাটনৰ প্ৰচেষ্টা দেখুওৱা হৈছে। এনে এখন চলচ্চিত্ৰ জনসাধাৰণৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো উচিত নহয়।

তেওঁৰ মতে, ইতিহাসৰ এটা অন্ধকাৰ অধ্যায়ক গোপন কৰি ৰখাৰ সলনি নতুন প্ৰজন্মই সেই সময়ৰ ঘটনাৱলী জানিব লাগিব। সেই উদ্দেশ্যে দিল্লী শিখ গুৰুদ্বাৰা প্ৰবন্ধক সমিতি -এ বিভিন্ন গুৰুদ্বাৰা অঞ্চলত ছবিখন প্ৰদৰ্শনৰ লগতে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত জস্বন্ত সিং খালড়াৰ জীৱন আৰু অৱদান সন্দৰ্ভত আলোচনা সভা আয়োজনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

চলচ্চিত্ৰখন প্ৰথমে ‘পঞ্জাব ৯৫’ নামেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ২০২২ চনত ছবিখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ বৰ্ড-লৈ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰা হয়। কিন্তু ছবিখন বহু বছৰ ধৰি অনুমোদন নাপালে। সংবাদমতে, প্ৰথমে ৮৫টা আৰু পিছত ১২৭ দৃশ্য বা অংশ কাটি পেলোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল। নিৰ্মাতাসকলে সেই শৰ্ত মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত বিষয়টো আদালতলৈও গৈছিল। অৱশেষত ছবিখন অটিটিত মুক্তি পালেও সেয়া অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আঁতৰাই দিয়া হয়।

এই ঘটনাৰ পিছত অভিনেত্ৰী গুল পানাগ-এও সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ লিখিছে যে শৈশৱত তেওঁ পঞ্জাবৰ উগ্ৰবাদ আৰু হিংসাৰ কঠিন সময় স্বচক্ষে দেখিছে। নিৰীহ মানুহৰ হত্যা, আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ আৰু অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ স্মৃতি এতিয়াও তেওঁৰ মনত সজীৱ। তেওঁৰ মতে, অতীতৰ এনে বেদনাদায়ক অধ্যায়সমূহৰ ওপৰত কাহিনী কোৱা বা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ বন্ধ কৰি দিয়াটো কোনো সমাধান নহয়। ইতিহাসক লুকুৱাই নাৰাখি, তাৰ পৰা শিক্ষা লোৱাটো অধিক প্ৰয়োজনীয়।

জস্বন্ত সিং খালড়া কোন আছিল ?

জস্বন্ত সিং খালড়া পঞ্জাবৰ এজন বিশিষ্ট শিখ মানৱাধিকাৰ কৰ্মী আছিল। ১৯৮০ আৰু ১৯৯০ দশকত পঞ্জাবত সংঘটিত বুলি অভিযোগ থকা ভুৱা এনকাউণ্টাৰ আৰু অচিনাক্ত বুলি দেখুৱাই কৰা গোপন দাহ-সংস্কাৰৰ তথ্য তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি জনসমুখলৈ আনিছিল। তেওঁ অভিযোগ কৰিছিল যে বহু নিৰীহ যুৱকক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি অভিহিত কৰি আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰাৰ পিছত লাশসমূহ গোপনে দাহ কৰা হৈছিল।

১৯৯৫ চনত তেওঁ নিজেই ৰহস্যজনকভাৱে অপহৃত হয়। পিছত সিবিআই-ৰ তদন্তত তেওঁৰ অপহৰণ আৰু হত্যাৰ ঘটনাত কিছুমান আৰক্ষী বিষয়াৰ জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহে। এই ঘটনাত কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াক আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি বিহে।

বিতৰ্কৰ মূল প্ৰশ্ন

‘সতলজ’ক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কে পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে-ইতিহাসৰ বিতৰ্কিত আৰু বেদনাদায়ক ঘটনাৱলী কি শিল্প, সাহিত্য বা চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিব পৰা উচিত নে? একাংশই কয়, এনে কাহিনীয়ে অতীতৰ সত্য উন্মোচন কৰে আৰু সমাজক আত্মসমালোচনাৰ সুযোগ দিয়ে। আনহাতে, আন একাংশই এনে বিষয়বস্তু সামাজিক সংবেদনশীলতা আৰু আইন-শৃংখলাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সতৰ্কতাৰে উপস্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

বৰ্তমান ‘সতলজ’ কেৱল এখন চলচ্চিত্ৰ হৈ নাথাকি, মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা, ইতিহাসৰ নথিভুক্তিকৰণ আৰু গণতান্ত্ৰিক সমাজত শিল্পৰ ভূমিকাক লৈ চলি থকা বিস্তৃত বিতৰ্কৰো প্ৰতীক হৈ পৰিছে।

নগৰীয়া জীৱনশৈলী আৰু স্থূলতা

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

বৰ্তমান সময়ত স্থূলতা কেৱল অধিক খোৱা বা ব্যায়াম নকৰাৰ ফল নহয়। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, নগৰীয়া জীৱনশৈলীৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনে মানুহৰ দৈনন্দিন অভ্যাস সলনি কৰিছে, আৰু সেই সলনি অভ্যাসেই স্থূলতাৰ নতুন কাৰণ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। হৃদৰোগ, ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ, ষ্ট্ৰোক আদি অসংখ্য অসংক্ৰামক ৰোগৰ অন্যতম মুখ্য ঝুঁকি হিচাপে স্থূলতাই ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে।

এণ্ডক্ৰাইনলজী বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, শেহতীয়াকৈ নগৰবাসীৰ মাজত বিশেষকৈ তিনিটা নতুন কাৰকে স্থূলতাৰ সমস্যা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে-দীৰ্ঘ সময় ডেস্কত বহি কাম কৰা, ফুড ডেলিভাৰী এপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা আৰু ‘স্লিপ ডেবট’ অৰ্থাৎ নিয়মীয়াকৈ পৰ্যাপ্ত নিদ্ৰাৰ অভাৱ।

ডেস্ক জব: দিনভৰ বহি থকাৰ ক্ষতি

ডিজিটেল যুগত অধিকাংশ চাকৰি কম্পিউটাৰ বা লেপটপক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছে। ফলস্বৰূপে বহু লোক দিনে ৮-১০ ঘণ্টা একে ঠাইতে বহি কাম কৰে। এই অভ্যাসৰ ফলত শৰীৰৰ শক্তি ব্যয় যথেষ্ট কমি যায় আৰু অতিৰিক্ত কেলৰী চৰ্বি হিচাপে

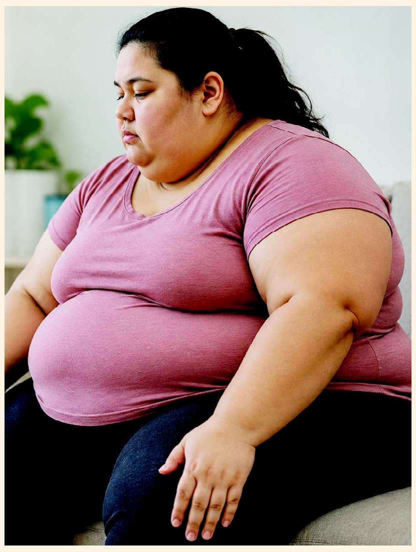

জমা হয়।

গৱেষণাই দেখুৱাইছে যে দিনভৰ বহি থকাৰ ক্ষতি কেৱল সন্ধিয়াৰ এঘণ্টা ব্যায়ামে সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। দীৰ্ঘ সময় বহি থকাটো নিজেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্যঝুঁকি, যিয়ে স্থূলতাৰ লগতে উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে।

ফুড ডেলিভাৰী এপ: সুবিধাৰ লগে লগে স্বাস্থ্যৰ সংকট

আগতে বাহিৰৰ খাদ্য খাবলৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ যাব লাগিছিল। এতিয়া মোবাইল ফোনৰ কেইটামান স্পৰ্শতেই ঘৰতে পিজ্জা, বাৰ্গাৰ, ফ্ৰাইড স্নেক, মিঠা পানীয় আৰু বিভিন্ন প্ৰচেছড খাদ্য আহি উপস্থিত হয়।

ব্যস্ত জীৱনশৈলীৰ বাবে বহুতে ঘৰুৱা পুষ্টিকৰ আহাৰৰ সলনি সহজলভ্য ফাষ্ট ফুডক বাছি লয়। এই ধৰণৰ খাদ্যত অধিক কেলৰী, লৱণ, চেনি আৰু অস্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি থাকে। নিয়মীয়াকৈ এনে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে শৰীৰত অতিৰিক্ত কেলৰী জমা হৈ ওজন দ্ৰুত বৃদ্ধি পায়।

‘স্লিপ ডেবট’: অদৃশ্য কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ

আধুনিক জীৱনত মোবাইল ফোন, সামাজিক মাধ্যম, অটিটি প্লেটফৰ্ম আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ চাপৰ বাবে বহু লোকেই নিয়মীয়া নিদ্ৰাৰ পৰা বঞ্চিত হয়। বহুতে সপ্তাহজুৰি কম শুই সপ্তাহান্তত অধিক সময় শুই এই অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ই সম্পূৰ্ণ সমাধান নহয়।

পৰ্যাপ্ত নিদ্ৰাৰ অভাৱত ক্ষুধা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ঘ্ৰেলিন আৰু লেপ্টিন হৰমনৰ ভাৰসাম্য বিঘ্নিত হয়। ফলত অধিক ভোক লাগে আৰু বিশেষকৈ মিঠা বা উচ্চ কেলৰিযুক্ত খাদ্যৰ প্ৰতি আকাংক্ষা বৃদ্ধি পায়। একে সময়তে ক্লান্তিৰ বাবে শাৰীৰিক সক্ৰিয়তাও হ্ৰাস পায়, যাৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত হয়।

তিনিওটা কাৰণৰ যৌথ প্ৰভাৱ

এজন নগৰীয়া কৰ্মজীৱী ব্যক্তিৰ দৈনন্দিন জীৱন কল্পনা কৰিলে সমস্যাটো স্পষ্ট হয়। দিনভৰ ডেস্কত বহি কাম, সন্ধিয়া ফুড ডেলিভাৰী এপৰ জৰিয়তে উচ্চ কেলৰিযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ আৰু নিশা দেৰিলৈ জাগি থকাৰ অভ্যাস-এই তিনিওটা কাৰণ একেলগে স্থূলতাৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে।

এই চক্ৰটো যদি দীঘলীয়া সময় ধৰি চলি থাকে, তেন্তে ওজন বৃদ্ধি, মেটাবলিক ৰোগ আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

সমাধানো আধুনিক জীৱনশৈলীৰ লগত খাপ খোৱা হব লাগিব

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, কেৱল ডায়েটিং বা জিম কৰিলেই এই সমস্যাৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান নহয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে দৈনন্দিন জীৱনত কিছুমান সৰু কিন্তু ফলপ্ৰসূ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব-

- প্ৰতি ঘণ্টাত কেইমিনিটমান উঠি খোজ কঢ়া।
- প্ৰতিদিনে অন্ততঃ ৩০-৪৫ মিনিট নিয়মীয়া শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰা।
- ফুড ডেলিভাৰী এপ ব্যৱহাৰ কৰিলেও পুষ্টিকৰ খাদ্য বাছনি কৰা।
- প্ৰতিদিনে ৭-৮ ঘণ্টা মানসম্পন্ন নিদ্ৰা নিশ্চিত কৰা।
- স্ক্ৰীণ টাইম কমাই নিয়মীয়া জীৱনশৈলী গঢ়ি তোলা।

"Success is not about being the best. It is about becoming better than you were yesterday."

VOICE OF ALL, FOR ALL
WEEKLY
JAN JAN VICHAR
Guwahati, Friday, 10 July 2026

Guwahati Parks Get Costlier

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati

A family outing to one of Guwahati's favourite parks will cost more than before. The Assam government has announced a revised entry fee structure for several major parks, gardens, and tourist attractions across the city, arguing that the increase is necessary to improve maintenance, cleanliness, security, and visitor facilities.

The decision reflects a broader trend in urban management: as cities expand and public spaces witness heavier footfall, governments are increasingly looking at user charges to ensure sustainable upkeep.

Why the Fee Hike?

Officials say the additional revenue will be used to maintain landscaped gardens, improve sanitation, strengthen security, repair infrastructure, and enhance visitor amenities. Parks today require regular investment in lighting, pathways, children's play areas, waste management, and landscaping-costs that have risen considerably over the years.

The government believes that a modest increase in entry fees will help reduce dependence on public funds while ensuring that these recreational spaces remain attractive and well-maintained.

Public Reaction: Divided Opinions

The announcement has generated mixed responses among city residents.

Many citizens support the move, saying clean, safe, and well-maintained parks deserve adequate funding. If the additional revenue translates into better toilets, improved landscaping, regular maintenance, and enhanced security, visitors may consider the higher charges worthwhile.

Others, however, worry that the increased fees could discourage low-income families, students, and senior citizens from visiting public parks regularly. Public parks have traditionally served as affordable recreational spaces where people can walk, exercise, relax, and spend quality time with family.

Several residents have suggested introducing discounted monthly passes, concessional rates for students and senior citizens, or free entry during morning and evening walking hours.

Beyond Revenue

Urban planners note that parks are not merely tourist attractions-they are essential public assets. Green spaces improve air quality, reduce urban heat, promote physical activity, and contribute to mental well-being. As Guwahati continues to grow rapidly, preserving and improving these spaces becomes increasingly important.

However, experts also argue that any fee increase should be matched by visible improvements. Visitors are likely to accept higher charges only if they experience cleaner surroundings, better facilities, accessible infrastructure, and consistent maintenance.

A Test for Urban Governance

The revised pricing policy places greater responsibility on civic authorities. Citizens will closely watch whether the additional revenue genuinely enhances the visitor experience or simply increases the cost of accessing public spaces.

The success of this initiative will ultimately depend not on the amount collected but on how transparently and effectively it is spent.

Public parks are investments in a city's health and quality of life. Charging reasonable entry fees is understandable if the money is used responsibly. But these spaces must remain accessible to every section of society. Better facilities should never come at the cost of excluding ordinary citizens from enjoying the city's green lungs.

REVISED ENTRY FEES

Location	New Entry Fee
Jorpukhuri Park	Rs 20
Gandhi Mandap	Rs 20
Amrit Udyan	Rs 30
Atal Udyan	Rs 30
Shraddhanjali Kanan	Rs 30
Nehru Park	Rs 50
Botanical Garden	Rs 60
Sati Radhika Shanti Udyan	Rs 60
Brahmaputra River Front	Rs 60
River Heritage Centre	Rs150
Guwahati Ropeway	Rs 250

Meghalaya CM Raises FCRA Concerns with Amit shah

New Delhi/Shillong: Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma met Union Home Minister Amit Shah in New Delhi to discuss concerns regarding certain provisions of the proposed amendments to the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA).

The Chief Minister was accompanied by senior representatives of several Christian organisations, including the Presbyterian Church of India, the North East India Christian Council (NEICC), the Catholic Church (Archdiocese of Shillong), and the Garo Baptist Convention. During the meeting, the delegation conveyed its concerns over the proposed changes to the FCRA and their possible impact on religious, educational, charitable and social welfare institutions operating across Meghalaya.

According to a statement issued by the Chief Minister's Office, these institutions manage a large network of schools, colleges, hospitals and community welfare programmes, particularly in rural and remote areas of the state, where they play a crucial role in providing essential services.

Two Assam Rifles Personnel Killed in Manipur

Imphal : Two personnel of the Assam Rifles were killed in an ambush in Manipur's Ukhrul district on 6th July, highlighting the continuing security challenges in the violence-affected state.

Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla strongly condemned the attack, describing it as a 'dastardly act of violence' and paid tribute to the slain security personnel.

In an official statement issued from Raj Bhavan, the Governor expressed deep sorrow over the loss of the two brave Assam Rifles personnel. He said such acts of violence have no place in society and cannot weaken the collective resolve to maintain peace and security in the state.

The Governor extended his heartfelt condolences to the bereaved families and prayed for strength and courage for them during this difficult time. He also wished a speedy recovery to those injured in the incident.

Security agencies have not yet disclosed detailed information regarding the circumstances of the ambush, and an investigation is underway. Additional security measures have reportedly been initiated in the area.

The latest attack comes against the backdrop of the prolonged ethnic unrest that has affected Manipur since May 2023. The violence, which initially erupted between the Meitei and Kuki communities, has claimed hundreds of lives, displaced thousands of people, and posed persistent challenges to law enforcement and security forces. More recent tensions have also involved other communities in certain parts of the state.

The incident once again underscores the urgent need for sustained peace-building efforts, stronger security measures, and continued dialogue to restore normalcy in Manipur.

Assam School Enrolment Decline Linked to Falling Birth Rate, Data Cleanup: Ranoj Pegu

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati

Assam Education Minister Ranoj Pegu has dismissed allegations that government schools in the state have witnessed a massive decline in student enrolment, describing the claims as 'misleading' and 'mathematically impossible.'

Responding to allegations made by Akhil Gogoi that over 2.12 lakh students had dropped out of government schools in the last two years and nearly 25.68 lakh students had disappeared between 2021-22 and 2024-25, Pegu said the figures do not reflect the actual situation.

The minister explained that Assam's overall school enrolment

has declined by 4.1 per cent, slightly lower than the national decline of 4.4 per cent. He attributed the reduction mainly to two factors: a declining birth rate and the ongoing cleanup of the Unified District Information System for Education (UDISE) database.

According to Pegu, the Education Department has been verifying enrolment records over the past three years and has removed nearly three lakh unverified or 'ghost' student entries, resulting in more accurate data.

Rejecting the claim that Assam had lost nearly half of its students, he said the state has approximately 50 lakh school-going children, making the allegation of a 25-lakh decline unrealistic.

The minister also pointed to Assam's falling Total Fertility Rate (TFR), which is now 1.9, slightly below the national average of 2.0. He said fewer births in recent years have naturally reduced enrolment in pre-primary and primary classes.

At the same time, Pegu highlighted a positive trend in higher classes. Enrolment in Classes IX to XII has increased by around 10,000 students, registering a 0.9 per cent growth, while secondary school enrolment has declined nationally. Addressing concerns over school closures, the minister clarified that only a limited number of institutions had been merged as part of the government's school rationalisation programme. He added that Assam continues to have around 44,000 schools across the state.

The government maintains that the decline in enrolment reflects demographic changes and improved data accuracy rather than a weakening of the state's education system.

1.72 Lakh Illegal Foreigners Detected

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati

Assam has identified 1.72 lakh illegal foreigners, of whom more than 31,700 have been repatriated so far, Chief Minister Himanta Biswa Sarma informed the Assam Legislative Assembly.

Replying to questions raised by legislators during the Assembly session, the Chief Minister, who also holds the Home portfolio, presented data on law and order, crime, and the state's action against illegal immigration.

According to the government, Assam Police have registered 9,68,938 criminal cases across the state since 2016. Of these, 5,20,782 cases have been chargesheeted, accounting for nearly 54 per cent of all registered cases.

Responding to another query, the Chief Minister said that 2,04,134 cases of crimes against women were registered in the state over the last ten years. These included 2,961 murders of women and 15,397 rape cases. Police have filed chargesheets in 1,33,675 of these cases. The Chief Minister further informed the House that since assuming office in 2021, 3,78,483 First Information Reports (FIRs) have been registered across Assam. During the same period, police arrested 4,26,502 accused persons, while 29,164 individuals were convicted by courts in connection with various criminal cases.

On the issue of illegal immigration, the government said that detection and deportation of illegal foreigners remain an important priority, with over 31,700 individuals already repatriated after due legal procedures.

The data presented in the Assembly reflects the government's emphasis on strengthening law enforcement, improving criminal justice delivery, and continuing efforts to address illegal immigration in the state.

Two New Gauhati High Court Benches

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati

In a significant step towards improving access to justice, the Assam Government has announced that new benches of the Gauhati High Court will be established in Dibrugarh and Barak Valley. The announcement was made by Assam Law Minister Susanta Borgohain during the Budget Session of the State Assembly.

The proposed benches are expected to benefit thousands of litigants from Upper Assam and Barak Valley by reducing travel time, lowering legal expenses, and ensuring quicker access to judicial services. The move also fulfils a long-pending demand of lawyers, civil society groups and residents, particularly in Barak Valley, where campaigns for a permanent High Court bench have continued for decades. However, the government has not announced any timeline for setting up the benches or clarified their territorial jurisdiction and operational framework. The Gauhati High Court currently functions from its principal seat in Guwahati and serves four northeastern states.

4.35 km of Assam Bangladesh Border Still Unfenced

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati

The Assam Government informed the Legislative Assembly that 4.35 kilometres of the India-Bangladesh international border in the state remains unfenced due to objections raised by the Border Guard Bangladesh (BGB).

Replying to a question in the House, Border Protection and Development Minister Atul Bora said that barbed-wire fencing has been completed along 228.541 kilometres of Assam's 267.5-kilometre international border with Bangladesh.

The minister stated that the unfenced 4.35-km stretch is located along the Kushiyara River in Sribhumi district, where Indian citizens live close to the riverbank. Construction of fencing in this area has been delayed due to objections raised by the Border Guard Bangladesh.

He further informed the Assembly that 34.609 kilometres of the border remain unfenced because they pass through riverine areas. Of this, 30.37 kilometres lie in Dhubri district and 4.239 kilometres in South Salmara-Mankachar district.

To strengthen border security in these open river stretches, the Border Security Force is using the Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS) along with boat observation outposts to monitor cross-border movement and prevent illegal activities.

Assam shares a 267.5-kilometre international border with Bangladesh across the districts of Dhubri, South Salmara-Mankachar, Cachar and Sribhumi.

The government reiterated that border fencing and surveillance remain key priorities for ensuring national security while addressing challenges posed by difficult terrain and international coordination.

Separatist Narratives Reach Government School Libraries

J&K Suspends 9 Officials, Bans Controversial Books

Jan Jan Vichar
...✍Srinagar

A major controversy has erupted in Jammu and Kashmir after two books allegedly glorifying separatist leaders and convicted terrorists were found in government school libraries. The discovery has raised serious questions over the screening of educational material supplied to students.

Government Acts Swiftly

The Jammu and Kashmir administration, under Lieutenant Governor Manoj Sinha, suspended nine officials of the School Education Department, withdrew the books from all government schools, and banned their authors and publishers pending further action.

Books Under Scanner

The two books 'Personalities and Legends of J&K' and 'Great Personalities of Jammu and Kashmir'-allegedly carried favourable references to Maqbool Bhat, Syed Ali Shah Geelani, Masarat Alam and Mirwaiz Umar Farooq. Their presence in school libraries has triggered a nationwide debate on educational accountability.

Officials Held Responsible

The School Education Department stated that the books contained 'highly inappropriate content' and blamed officials for negligence, dereliction of duty and failure to conduct proper due diligence before approving them for government school libraries.

Nine Face Action

Eight permanent officials have been suspended under the Jammu and Kashmir Civil Services Rules, while one contractual employee has been removed from service with immediate effect.

High-Level Inquiry Ordered

To determine how the books entered government schools, the administration has appointed senior IAS officer Ashwani Kumar to conduct a detailed inquiry into the approval, procurement and distribution process.

Political War Begins

The issue has quickly turned political. BJP leader and Leader of the Opposition Sunil Sharma described the episode as 'academic jihad', alleging an attempt to influence young minds through educational material. Opposition parties are yet to present a detailed response.

A Bigger Question

The controversy raises an important national concern: Who ensures that educational resources used in schools remain free from ideological bias and anti-national narratives? Experts say stronger scrutiny and transparent review mechanisms are essential to safeguard the integrity of school education.

Education shapes the future of a nation. While history should encourage critical thinking, no educational material meant for children should glorify violence, terrorism or separatism. Accountability in textbook selection is not merely an administrative duty-it is a national responsibility.

Oil Giant Turns Buyer: Russia Is Importing Fuel

Jan Jan Vichar
...✍Moscow

In a development that highlights the far-reaching impact of the Russia–Ukraine war, Russia—one of the world's largest crude oil producers and exporters-has increasingly turned to importing refined petroleum products to meet domestic demand after repeated attacks on its refining infrastructure.

The situation has surprised global energy markets. A country that supplies millions of barrels of crude oil to the world is now purchasing fuel from friendly nations to compensate for the loss of refining capacity at home.

Why Is Russia Importing Fuel?

Russia remains one of the world's leading producers of crude oil. However, crude oil must be processed in refineries before it becomes petrol, diesel, aviation fuel and other usable products.

Since the outbreak of the war, several Russian refineries have reportedly been damaged or temporarily shut down following long-range drone attacks attributed to Ukraine. While not all refineries have been destroyed, repeated strikes have disrupted operations, reducing Russia's ability to produce enough refined fuel for domestic consumption.

Refineries Under Pressure, Not Wiped Out

Contrary to claims circulating on social media, Ukraine has not destroyed all Russian refineries. Russia continues to operate many major refining facilities.

However, attacks on multiple refineries over the past two years have caused periodic shutdowns, repair work and reduced production. These disruptions have occasionally forced Moscow to import limited quantities of refined petroleum products while continuing to export crude oil.

War Changes Energy Priorities

The conflict has transformed energy into a strategic weapon. Both Russia and Ukraine have targeted energy infrastructure in an attempt to weaken each other's economic and military capabilities.

For Russia, maintaining fuel supplies for civilians, industries and the armed forces has become a priority. Temporary imports help bridge supply gaps created by refinery outages.

Sanctions Add to the Challenge

Western sanctions imposed after the invasion of Ukraine have complicated Russia's energy trade by restricting access to technology, finance and international markets. Although Russia has redirected much of its crude exports to countries such as India and China, repairing damaged refining facilities has become more difficult and costly.

Global Markets Watching Closely

Energy analysts say the disruption underscores the difference between producing crude oil and refining it. A country may possess abundant oil reserves, but damage to refineries can still create shortages of petrol and diesel.

China–Russia Naval Drill

Beijing : China and Russia are set to begin a week-long joint naval exercise in the waters near Qingdao from July 6 to July 13, underlining the growing strategic partnership between the two powers. The exercise, involving warships, submarines and aerial operations, comes at a time of heightened geopolitical tensions across the Indo-Pacific. Following the drills, selected naval units from both countries are expected to conduct joint maritime patrols in parts of the Pacific Ocean, according to official statements from the Chinese Defence Ministry and Russian state media. The annual exercise will feature coordinated operations at sea and in the air, testing interoperability between the Chinese and Russian navies. Russia has reportedly deployed a cruiser, a corvette, a diesel-electric submarine and a rescue vessel from its Pacific Fleet for the exercise.

Editorial

Strength of Passport

A passport is far more than a document that allows citizens to cross international borders. In today's interconnected world, it represents a nation's diplomatic standing, economic strength, governance, and the level of global trust it enjoys. India's ranking in the Global Passport Index 2026 has once again highlighted the need to view passport strength not merely as a travel convenience but as an important indicator of national competitiveness.

While different passport rankings use different methodologies, the message is clear: Indian citizens still face extensive visa requirements for many major destinations. Students, professionals, entrepreneurs, researchers, and tourists often encounter lengthy application procedures, high costs, and uncertainty before they can travel abroad. These hurdles affect not only individual aspirations but also India's global engagement.

Passport strength is built through diplomacy and mutual confidence between nations. Countries with the world's strongest passports have invested consistently in stable institutions, effective governance, secure borders, international cooperation, and strong bilateral relations. Their citizens benefit because other countries have confidence in their systems and policies.

India has made remarkable progress in recent years. It is one of the world's fastest-growing major economies, an important voice in global affairs, and a key partner in trade, technology, and security. These achievements provide a strong foundation for improving international mobility. However, greater diplomatic engagement, more reciprocal visa agreements, improved ease of doing business, stronger institutional credibility, and continued investments in education, healthcare, infrastructure, and public services will further enhance India's global standing.

The value of a passport ultimately depends on the reputation of the country behind it. As India's economic influence expands and its international partnerships deepen, the strength of the Indian passport should naturally improve. This requires sustained policy efforts rather than short-term measures.

For India, the passport ranking should not be viewed as a setback but as a policy benchmark. It offers an opportunity to strengthen diplomacy, improve governance, and reinforce the confidence that the world places in the country.

A stronger passport is not simply about travelling without visas-it is about building a nation whose credibility, stability, and achievements earn global respect.

Manipur's Expanding Fault Lines

Jan Jan Vichar
...✍Ajai Sahni

New Delhi's self-inflicted wound in Manipur has deepened. The devastating confrontation engineered between the Meitei and Kuki-Zo communities has evolved into a far more complex crisis, with the fractured security landscape compounded by growing Kuki-Naga conflict. The killing of three tribal church pastors from the Thadou Baptist Association of India while they were returning from peace talks on May 13, resulted in retaliatory abductions, and the subsequent killing of six abducted Naga civilians by Kuki insurgents, despite the safe return of Kuki abductees by Naga groups, demonstrating how rapidly the conflict had descended into increasingly barbaric forms. As identity politics is weaponised and ethnic hatred normalised, violence is inflating well beyond its original protagonists.

Three years after the ethnic violence erupted in May 2023, Manipur remains physically divided, thousands remain displaced, villages have been destroyed, livelihoods disrupted, and confidence in state institutions is virtually non-existent. Massive deployments of Central security forces have prevented an even greater catastrophe, but military containment cannot substitute for political resolution.

Kuki-Naga tensions in Manipur have a long history, and periodic low-grade conflict is not unusual over contested territories and political frictions. Indeed, between 1992 and 1997, escalating violence between militant elements of the two groups resulted in hundreds of fatalities, though the conflict thereafter remained largely dormant or sporadic. The current crisis, however, overlaps with a collapse of government authority and credibility, as well as public trust, with non-state armed actors steadily expanding their role and influence.

> Three years after the ethnic violence erupted in May 2023, Manipur remains physically divided, thousands remain displaced, villages have been destroyed, livelihoods disrupted, and confidence in state institutions is virtually non-existent. Massive deployments of Central security forces have prevented an even greater catastrophe, but military containment cannot substitute for political resolution.

Crucially, simmering disputes were transformed into sustained ethnic warfare as a result of the systematic mobilisation of ethnic hatred and fear by political actors, militant organisations and sections of civil society that have increasingly sought to harness a vicious and polarising identity politics.

The descent into mutually reinforcing hatred in Manipur represents one of the gravest failures of democratic politics in India since Independence. Instead of moderating conflict, reassuring competing communities and preserving confidence in the neutrality of the state, the political leadership, both Central and State, did the opposite, inflaming passions and destroying faith in administrative impartiality. Administrative decisions are now viewed through ethnic lenses, political rhetoric has deepened communal suspicions, and trust in public institutions has steadily evaporated. While the state government was essentially part of the mischief that provoked the initial conflagration, the Union Government failed to articulate a credible political roadmap capable of rebuilding trust among Manipur's fractured communities. Massive deployments of Central security forces may suppress violence, but they cannot reconcile communities. Without sustained political engagement, ethnic segregation and the extremist narrative has strengthened month after month, making coexistence virtually impossible.

The consequences extend beyond Manipur. Bordering an unstable Myanmar, the state lies astride expanding narcotics trafficking networks and long-established insurgent corridors that exploit weak governance and porous frontiers. Continuing political fragmentation is creating vulnerabilities extending across India's fragile Northeast.

The symbolic character of the recent violence is particularly disturbing. The murder of church leaders engaged in peace initiatives sends an unmistakable message that moderation itself has become a target. Those seeking dialogue increasingly find themselves threatened by extremists on all sides whose political relevance depends on perpetuating fear and radical communal mobilisation. Every successful effort at reconciliation weakens the influence of armed organisations and ethnic entrepreneurs; every fresh atrocity strengthens their claim that coexistence has become impossible. The killing of religious leaders was not merely another criminal act but an assault on the very possibility of political reconciliation

Manipur today suffers not merely from ethnic division but from a collapse of political responsibility. The killing of peace emissaries, the descent into reciprocal hostage-taking and the murder of abducted civilians should dispel any illusion that the crisis is a conventional law-and-order problem. The conflict is becoming progressively more fragmented, more communal, and more resistant to resolution. Unless India's political leadership rejects the cynical politics of hatred and restores confidence in constitutional governance, Manipur risks becoming a permanent theatre of overlapping ethnic conflicts whose consequences will reach far beyond the state's borders.

Jan Jan Vichar
The Student's Corner
Board Exam Focus

Real Numbers

General Mathematics // Class-10 //Chapter-1

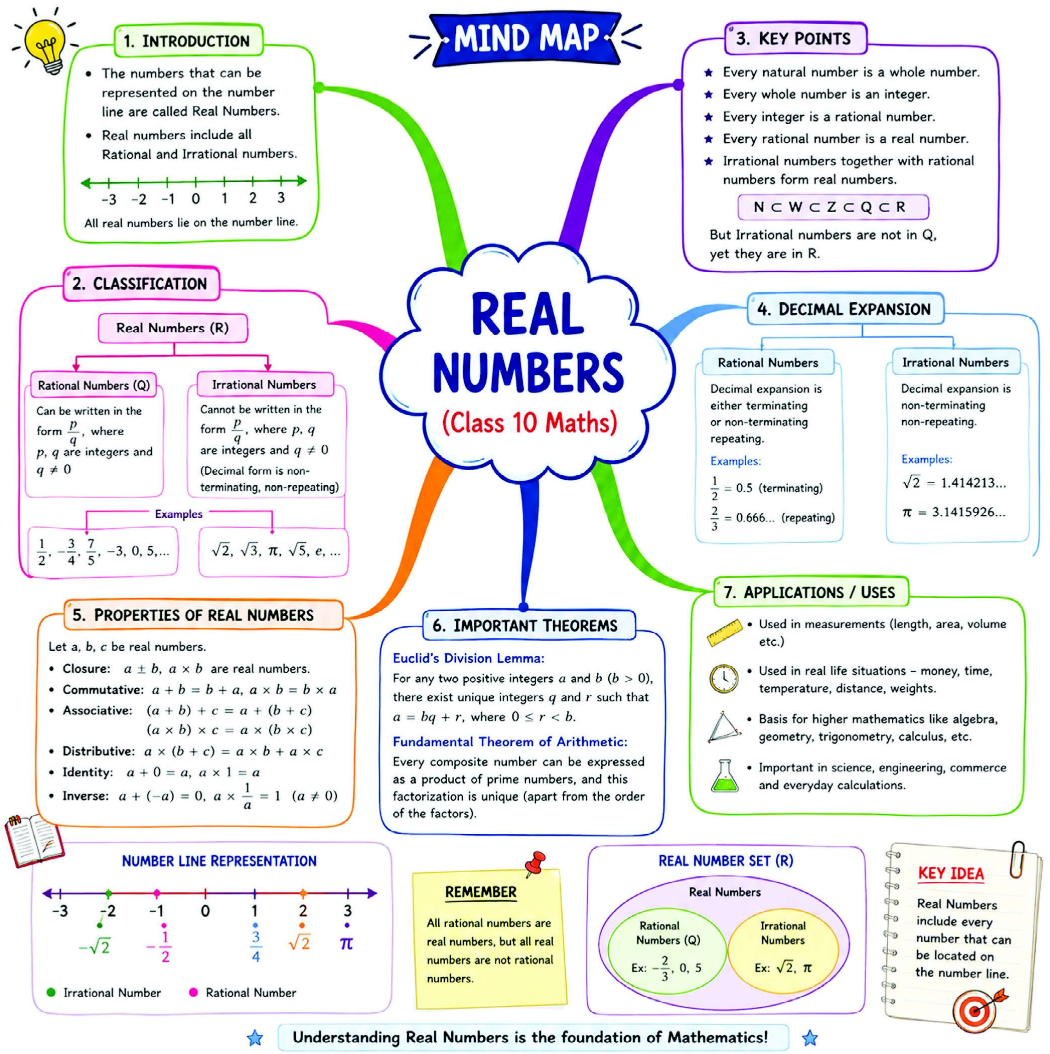

1. Real Numbers : A real number is any number that can be represented on the number line.

Types of Real Numbers

Rational Numbers : A rational number is a number that can be expressed in the form p/q where, p and q are integers, and $q \neq 0$.

Every integer is a rational number.

Rational numbers have terminating or non-terminating recurring (repeating) decimal expansions.

Irrational Numbers : An irrational number is a number that cannot be expressed in the form p/ q, where p and q are integers and $q \neq 0$. Its decimal expansion is non-terminating and non-recurring.

2. Prime and Composite Numbers

Prime Number: Has exactly two factors (1 and itself). Examples: 2, 3, 5, 7, 11

Composite Number: Has more than two factors. Examples: 4, 6, 8, 9, 12

Note: 1 is neither prime nor composite.

3. Fundamental Theorem of Arithmetic (FTA) : Every composite number can be expressed as a product of prime numbers in a unique way, except for the order of the factors.

Examples

$60=2^2\times3\times5$ $540=2^2\times3^3\times5^4$

Finding HCF and LCM using Prime Factorisation

HCF: Take the common prime factors with the smallest powers.

LCM : Take all prime factors with the greatest powers.

Find HCF and LCM of 24 and 36.

$24=2^3\times3$ $36=2^2\times3^2$

$HCF=2^2\times3=12$ $LCM=2^3\times3^2=72$

5. Relation between HCF and LCM

For two numbers,

HCF×LCM=Product of the numbers

Example: HCF= 12, LCM = 72

12×72=864, which equals 24×36=864

6. Important Word Problems

(a) Largest number dividing two numbers leaving the same remainder -Subtract the remainder first. Then find the HCF.

(b) Smallest number leaving the same remainder-Find the LCM. Add the remainder.

(c) Smallest number leaving different remainders-Convert to a common form, then find the LCM.

(d) Number increased by a given value becomes divisible-

Required Number=LCM-Increase

(e) Equal distribution / Minimum number of rooms / Largest equal group-Always use HCF.

7. Irrational Numbers : The word irrational means 'not expressible as a ratio'. Since every rational number can be written as a ratio of two integers, numbers that cannot be written in this form are called irrational numbers.

Decimal Representation

Rational Number : 1/3 =0.3333333…

The digits repeat. Hence, it is rational.

Some Important Problems

Section A (1–2 Marks)

1. State the Fundamental Theorem of Arithmetic.
2. Express 540 as a product of prime factors.
3. Find the HCF and LCM of 24, 36 and 40 using prime factorisation.
4. Find the HCF and LCM of 30, 72 and 432.
5. Verify that"HCF × LCM = Product of the two numbers"for 404 and 96.

Section B (2–3 Marks)

1. The HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one number is 161, find the other.
2. The HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175. If one number is 725, find the other.
3. The HCF of two numbers is 18 and their product is 12960. Find their LCM.
4. The HCF of two numbers is 5 and their LCM is 200. Find the product of the numbers.
5. The LCM of two numbers is 9 times their HCF. Their sum is 500. Find their HCF.

Section C (Competency-Based)

1. Find the largest number that divides 438 and 606 leaving remainder 6 in each case.
2. Find the largest number that divides 320 and 457 leaving remainders 5 and 7 respectively.
3. Find the smallest number which when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder 7 in each case.
4. Find the smallest number which when divided by 28 and 32 leaves remainders 8 and 12 respectively.
5. Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by 468 and 520.

Section D (Case/Application-Based)

1. In a seminar, there are 60 Hindi, 84 English and 108 Mathematics participants. Find the minimum number of rooms if each room has the same number of participants and only one subject per room.
2. Three pieces of timber 42 m, 49 m and 63 m long are cut into equal lengths.
Find-
a) the greatest possible length of each plank,
b) the total number of planks.
3. Find the maximum number of students among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed equally.

Section E (Proof-Based)

1. Prove that $\sqrt{2}$ is irrational.
2. Prove that $3+2\sqrt{5}$ is irrational.

Irrational Number :

$\sqrt{2}$ =1.414213562373095…

The digits neither stop nor repeat. Hence, it is irrational.

If **n** is not a perfect square, then $\sqrt{n}$ is irrational

Examples $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{10}$, are irrational.

If $\sqrt{n}$ is irrational, then $a+b\sqrt{n}$ (where a and b are rational numbers and b≠0) is also irrational.

Nature's Palette: Six Ancient Indian Dyes That Coloured the World

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati

Long before synthetic dyes transformed the textile industry, India had already earned global recognition as the land of natural colours. From the cities of the Indus Valley Civilization to the royal courts of the Mughals, Indian artisans mastered the art of extracting vibrant dyes from plants, roots, bark and spices. These eco-friendly colours not only beautified fabrics but also became valuable commodities in international trade, attracting merchants from Rome, Persia, Arabia and beyond.

Here are six remarkable natural dyes that showcase India's rich heritage of colour.

1. Turmeric-The Golden Yellow

Turmeric (Curcuma longa) has been treasured in India for thousands of years, not only as a medicinal herb but also as a brilliant natural dye. Its bright golden-yellow colour symbolised purity, prosperity and spirituality. Ancient Indians used turmeric to dye ceremonial garments, sacred fabrics and festive attire. Even today, turmeric remains an integral part of Indian religious rituals and traditional textile practices.

2. Indigo – The Blue Gold

Known as 'Blue Gold', indigo revolutionised the global textile industry. Extracted from the leaves of Indigofera tinctoria, this deep blue dye originated in ancient India and became one of the country's most valuable exports. Roman nobles admired Indian indigo, while traders carried it across Asia, Africa and Europe. The modern denim industry owes much of its heritage to this remarkable Indian invention.

3. Walnut Brown

The bark, leaves and husks of walnut trees provided rich shades of brown and black. During the Mughal period, artisans extensively used walnut dye for colouring Kashmiri shawls, carpets and luxurious woollen fabrics. Naturally rich in tannins, walnut dye produced durable colours that resisted fading and gave textiles an elegant appearance.

4. Henna – The Festive Red-Brown

Henna, obtained from the leaves of Lawsonia inermis, has been an essential part of Indian culture for centuries. Besides decorating hands and feet with intricate designs, it was widely used to colour hair and fabrics. Its cooling properties and long-lasting reddish-brown shade made it especially popular during festivals and royal celebrations.

5. Saffron – The Royal Hue

Few natural dyes were as precious as saffron. Derived from the delicate stigmas of the saffron crocus, it produced a radiant orange-yellow colour associated with royalty, sacrifice and spirituality. Because of its rarity and high value, saffron-dyed garments were reserved for kings, nobles and revered spiritual leaders.

6. Indian Madder – The Lasting Crimson

The roots of Indian madder (Rubia cordifolia), known as Manjistha in Ayurveda, produced beautiful shades of red and pink. Highly valued for its exceptional colour fastness, madder dye helped Indian cotton textiles gain worldwide fame. Its vibrant and long-lasting colours made Indian fabrics among the most sought-after products in ancient global trade.""A Legacy Worth Preserving""India's mastery of natural dyes reflects the country's deep understanding of nature, chemistry and craftsmanship. These plant-based colours were biodegradable, environmentally friendly and remarkably durable—qualities that modern industries are once again beginning to appreciate.""As the world moves towards sustainable fashion and eco-friendly production, India's ancient dyeing traditions offer timeless inspiration. The colours that once travelled the Silk Route and adorned royal courts continue to remind us that India's greatest innovations often came directly from nature itself.

Aamir Khan Weds Gauri Spratt

Bollywood actor Aamir Khan and Gauri Spratt have tied the knot in an intimate ceremony attended by family and close friends. Newly released videos show the couple signing their marriage documents, with Aamir kissing Gauri's hand, embracing her warmly and dancing joyfully to celebrate their new beginning. The private wedding was attended by several prominent guests, including Mukesh Ambani, Raj Thackeray and filmmaker Rajkumar Hirani. The heartwarming moments from the ceremony have quickly gone viral on social media.

Printed & Published by Purvanchal Prints, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati-781005 Contact: 69001 26012
Email : Official.janjanvichar@gmail.com, Website : www.janjanvichar.in ● Executive Editor : Subhash Kumar Choudhary ● Editor : Dhaneshwar Choudhary